वर्ष-15, अंक-157
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

इंदौर, बुधवार 11 सितम्बर 2024

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

आज का विचार

हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा।

अजमेर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश, ट्रैक पर दो जगह रखे वजनी ब्लॉक

अजमेर। कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर जिले में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई है। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि राजस्थान में ट्रेन को बेपटरी करने की यह साजिश तीसरी बार अंजाम दी गई है। जानकारी के अनुसार मामला रविवार रात का है जब फुलेरा से अहमदाबाद मार्ग मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी। इस मामले में मांगलियावास थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई है, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। रिपोर्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन (डीएफसीसी) कर्मचारी रवि बुंदेला और विश्वजीत दास ने दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार 8 सितंबर की रात 10.36 बजे सूचना मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वह टूटकर गिरा हुआ है। एक किमी आगे एक और ब्लॉक टूटकर साइड में रखा हुआ था। ये दोनों ब्लॉक अलग-अलग जगह पर रखे हुए थे। इसके बाद डीएफसीसी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मिलकर सराधना से बांगड़ ग्राम स्टेशन तक पेट्रोलिंग की, इस दौरान स्थिति सामान्य पाई गई

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र में सोशल मीडिया यूज करने पर लगेगी रोक?

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की सरकार सोशल मीडिया तक बच्चों की पहुंच के लिए न्यूनतम उम्र तय करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि सरकार जल्द ही बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने से रोकने के लिए उम्र सत्यापन तकनीक का परीक्षण करेगी। कई देश और अमेरिकी राज्य बच्चों को सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी ने वादा किया है कि अगले साल मई में चुनाव के बाद सत्ता में आने पर वह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगी। अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को बताया कि हमने इस वर्ष के अंत से पहले आयु सत्यापन के लिए कानून लाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हम युवाओं को सोशल मीडिया के नुकसान से दूर रख सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि कई युवाओं को ऐसी चीज से जूझना पड़ रहा है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं चलाना जानता था पति तो पत्नी ने करवा दी हत्या

ग्लालियर। ग्वालियर में हत्या और प्रेम का अनोखा मामला सामने आया है। महिला एडवांस पति चाहती थी। पति जो सोशल मीडिया पर एक्टिव, जिसे इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना आता हो। मगर पति की मोबाइल और सोशल मीडिया में बिल्कुल भी रूचि नहीं थी। इसी बीच महिला के ममेरे जेठ से अवैध संबंध बढ़ने लगे। जेठ भी अनपढ़ था, मगर सोशल मीडिया की ओलम, गिनती और ए बी सी डी... बखूबी जानता था। इसके बाद पत्नी की जेठ यानी सोशल मीडिया के हीरो से नजदीकियां बढ़ीं तो वहीं सोशल मीडिया के जीरो यानि उसके पति से दूरियां बढ़ने लगी थीं। बढ़ती दुरियों के चलते पत्नी ने आशिक संग पति को रास्ते से हटाने की सोची और उसको मौत के घाट उतार दिया। ग्वालियर के एसडीओ संतोष पटेल ने बताया है कि भिंड आलमपुर निवासी महावीर शरण कौरव की पत्नी ज्योति कौरव ने मामा के लड़के जेठ, सुरेंद्र कौरव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। ज्योति ने प्लान बनाया था कि पति को जेल में मिलने के बहाने ग्वालियर ले जाओ और फिर रास्ते में उसका काम तमाम कर दो। महावीर को उसके मामा का लड़का आरोपी सुरेंद्र कौरव, ग्वालियर जेल में बंद हत्या के प्रयास के आरोपी से मिलने का कहकर ले गया था। जेल में मिलने के बाद दोनों ग्वालियर से आलमपुर के लिए निकले। इसी बीच रास्ते में कई बार महावीर की पत्नी का फोन सुरेंद्र के पास आया। एकांत इलाका देखकर दोनों रुके और साथ में गाजा पिया। इस बीच सुरेंद्र ने महावीर के सिर पर पत्थर दे मारा। नशे में चूर महावीर की मौत हो गई।

सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में लिए गए कई अहम फैसले
शिप्रा नदी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए योजना

मंत्री ही होंगे निगम-मंडल अध्यक्ष

भोपाल। राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में फैसला लिया गया कि सभी निगम मंडलों में प्रमुख सचिव की जगह मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। अभी तक विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव उनके अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में बताया कि संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड इकाइयों का पुनर्गठन करने के लिए प्रशासनिक इकाई सुधार आयोग बनाया गया है। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में इस काम को देखें और जिन प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है, उसके संबंध में आमजन से चर्चा कर अनुशंसाएं आयोग को दें। बता दें कि दिसंबर 2023 में सरकार के गठन के बाद विभिन्न निगम और मंडलों के अध्यक्षों को हटा दिया गया था। राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने के कारण संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को अध्यक्ष का प्रभार सौंप दिया था। भारत माला परियोजना अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में बनाया जाएगा, जिसकी लागत 1111 करोड़ है। इसमें भारत और राज्य सरकार की राशि है। इससे 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका सुपरविजन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक पार्किंग, रेलवे सुविधा होंगी और अन्य व्यापारिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि कलेक्टर गाइडलाइन से कम होने के कारण किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि स्पेशल पैकेज के तहत सरकार द्वारा दी जाएगी। उज्जैन में शिप्रा नदी में निरंतर प्रवाह बना रहे, इसके लिए परियोजना 614 करोड़ की लागत से सेवर खेड़ी-सेलारखेड़ी परियोजना के तहत जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर जल क्षमता बढ़ाने के लिए काम करेंगेष डोकरी खेड़ा जलाशय में कमांड इलाके ने किसानों की लंबित मांग थी वहां पानी नहीं पहुंचता। लगभग 2950 हेक्टर रबी सिंचाई सुविधा मिलेगी। 50 करोड़ की लागत से काम होगा। इससे 65 गांव की कुल 18800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मर्ज होने के बाद अब चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय भी अब मर्ज होंगे। नए 18 पद बनेंगे और 36 पद खत्म होंगे। कुल 636 पद संचालनालय में होंगे ताकि प्रशासनिक तंत्र मजबूत हो। एमबीबीएस की अभी 125 सीट हैं अब 250 सीट हो जाएंगी।

मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का दावा

कोलंबस ने नहीं, भारतीयों ने की थी अमेरिका की खोज

भोपाल। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि भारत में छात्रों को इतिहास के बारे में बहुत से गलत तथ्य पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि न तो वास्कोडिगामा ने भारत की खोज की थी, और न ही उसने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की खोज भी कोलंबस ने नहीं की थी, बल्कि हमारे पूर्वजों ने की थी, जो सदियों पहले से वहां जाकर व्यापार कर रहे थे। ये बातें उन्होंने मंगलवार को भोपाल में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान कही। इस दौरान सभागार में प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। समारोह में परमार ने कहा कि भारत के इतिहास के बारे में गलत बातें पढ़ाई गईं। हमें बताया गया कि वास्कोडिगामा ने भारत की खोज की। उन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। जबकि ऐसा नहीं है, 1498 में जब वो भारत आए तो हमारे देश के एक गुजराती व्यापारी के पीछे-पीछे आए थे। वास्कोडिगामा ने एक दुभाषिए की मदद से भारतीय व्यापारी से कहा था कि मुझे भारत देखना है। इसके बाद चंदन नाम के उस व्यापारी ने कहा था कि मैं जाने वाला हूं आप मेरे पीछे-पीछे जहाज डाल देना। उन्होंने कहा कि क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले भारतीय अमेरिका पहुंच चुके थे, इसलिए मैं लोगों द्वारा लिखी गई बातों का खंडन करता हूं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यहां के लोग आठवीं शताब्दी में व्यापार के लिए अमेरिका जाते थे। मंत्री ने कहा, कोलंबस 1492 में अमेरिका गए थे, लेकिन हमारे देश के रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने आठवीं शताब्दी में ही अमेरिका के साथ व्यापार शुरू कर दिया था।

कोर्स से हाटाई जाएगी वास्कोडिगामा वाली बात

मप्र के पाठ्यक्रम में वास्कोडिगामा वाले तथ्य को संशोधित करने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री परमार ने कहा कि यह इतिहास में स्वयंसिद्ध हो चुका है कि वास्कोडिगामा ने भारत की खोज नहीं की थी और हम इसे हटा देंगे। भारत का इतिहास वास्कोडिगामा के देश के निर्माण से पहले भी अस्तित्व में था, इसलिए भारत की खोज का सवाल ही नहीं उठता। समारोह के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक और झूठ जिसे पढ़ाने की भारत में जरूरत नहीं थी कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को इससे कोई लेना-देना नहीं था। अगर पढ़ाना था तो यह भी पढ़ाते कि कोलंबस के पहुंचने के बाद वहां पहुंचे लोगों ने वहां के स्थानीय समाज पर किस प्रकार से अत्याचार किए, और वहां के जनजातीय समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गईं, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से ये सही तथ्य नहीं पढ़ाए गए और उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाया गया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की।

अमेरिका के सेनडियागो में बनाए मंदिर

परमार ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को लिखना था तो यह लिखना था कि भारत का महानाविक आठवीं शताब्दी में अमेरिका गया था और उसने अमेरिकी राज्य सेनडियागो में कई मंदिरों का निर्माण कराया था। इस बारे में वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं, वहां की लायब्रेरी में आज भी तथ्य रखे हुए हैं। अगर किसी को पढ़ाना ही था तो सही पढ़ाना था कि अगर किसी ने अमेरिका की खोज की है तो हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ मिलकर उनके विकास में सहयोग किया है, यही भारतीय दर्शन और चिंतन है, जिसे विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत थी।

अभी यह पढ़ाया जा रहा

फिलहाल पढ़ाए जाने वाले इतिहास के अनुसार 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अनजाने में अमेरिका की खोज कर ली थी, जबकि वह वास्तव में भारत के तट पर पहुंचना चाहता था। वहीं 20 मई, 1498 को वास्कोडिगामा कोझिकोड के पास कप्पड़ पहुंचे थे, जो उस समय कालीकट के जमोरिन (समुथिरी राजा) के राज्य का हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि केन्या के एक भारतीय ने डिगामा को उपमहाद्वीप का रास्ता बताने में मदद की थी तथा उन्हें मानसून के बारे में भी बताया था।

आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कोलकाता। चिकित्सक दुष्कर्म और हत्या मामले में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने मंगलवार शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना है। उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटेंगे। इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि काम पर लौटने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि काम पर लौटने पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या तबादले नहीं किए जाएंगे। आंदोलनकारी डॉक्टर्स में से एक ने कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं होने पर हम काम बंद करना जारी रखेंगे। हमने राज्य सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को शाम 5 बजे तक हटाने के लिए कहा था। जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव मिलने के कुछ घंटों बाद ही अपना काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया था।

अमेरिका में राहुल बोले- मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता...

नई दिल्ली। अमेरिका में छात्रों-शिक्षकों से बातचीत के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का एक संघ है, जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तो वे अपने देवता के साथ विलीन हो जाते हैं। यह भारत की प्रकृति है। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस की गलतफहमी यह है कि वे सोचते हैं कि भारत अलग-अलग चीजों का एक समूह है, मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। कई मौकों पर मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस के बहाने भाजपा पर कटाक्ष किया और कहा कि सत्ताधारी पार्टी यह नहीं समझती कि देश सबके लिए है, जबकि नागपुर में मुख्यालय रखने वाले उनके लिए केवल एक विचारधारा महत्वपूर्ण है। वर्जीनिया के हर्नडन में एक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने भारत की विविधता का उदाहरण देने के लिए भोजन की थाली में अलग-अलग व्यंजनों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाया कि आरएसएस का मानना है कि कुछ राज्य और समुदाय दूसरों से कमतर हैं। इसी बात को लेकर लड़ाई है। हमारा मानना है कि सभी का अपना इतिहास, परंपरा और भाषा है। उनमें से हर एक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। अगर कोई आपसे कहे कि आप तमिल नहीं बोल सकते तो आप क्या करेंगे? आपको कैसा लगेगा? आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? यही आरएसएस की विचारधारा है - कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी - सभी निम्न भाषाएं हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, लड़ाई इस बात पर है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं, जहां लोगों को वह मानने की अनुमति हो जो वे मानना चाहते हैं?... या हम ऐसा भारत चाहते हैं, जहां केवल कुछ लोग ही तय कर सकें कि क्या होने वाला है।

अब 108 एंबुलेंस को वाट्सएप से भी कर सकेंगे हैं बुक

भोपाल। मध्यप्रदेश के मरीजों की सुविधा के लिए प्रदेश में एंबुलेंस 108 का संचालन करने वाली कंपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। अब एक एक नई सेवा चालू की गई है जिसके अंतर्गत लोग 108 एंबुलेंस के लिए दिए गए वाट्सएप नंबर पर मैसेज डालकर एंबुलेंस को बुक कर सकते हैं। मैसेज डालने के बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएगी और आपके द्वारा फीड किया गया डेटा कंट्रोल रूम पर पहुंच जाएगा। वहां टीम द्वारा आपके लिए एंबुलेंस भेज दी जाएगी। इसके लिए यह वाट्सएप नंबर 6269695935 जारी किया गया है। मध्यप्रदेश में एंबुलेंस 108 का संचालन करने वाली कंपनी जै अंबे के सीनियर मैनेजर तरुण सिंह ने बताया कि बुखार उल्टी या दस्त लगना, चक्कर आना, गैस होना, पेट दर्द, लू लगना, शरीर दर्द, खुजली, त्वचा रोग, सड़क दुर्घटना, मिर्गी के दौरे, सीने में दर्द, हार्ट अटैक, किसी कीड़े जानवर के काटने पर, सांस लेने में दिक्कत, दम घुटना, मानसिक अस्वस्थता, पानी में डूबना, रोड लीडेंट, बर्न, अधिक दवा का सेवन, लकवा लगना, मानसिक दौरा, यूरीन सम्बन्धी समस्या और अन्य सभी मेडिकल सम्बंधित समस्या के लिए 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

साइबर ठगों पर नकेल कसेंगे 5000 साइबर कमांडो, बनेगा राष्ट्रीय पोर्टल

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कई नए कदमों की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने, एक वेब-आधारित डेटा रजिस्ट्री स्थापित करने और साइबर अपराध की जानकारी साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने का ऐलान किया है। गृह मंत्री शाह ने भविष्य में साइबर अपराधों को रोकने के लिए संदिग्धों की एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध कोई सीमा नहीं देखते इसलिए साइबर सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा असंभव है।

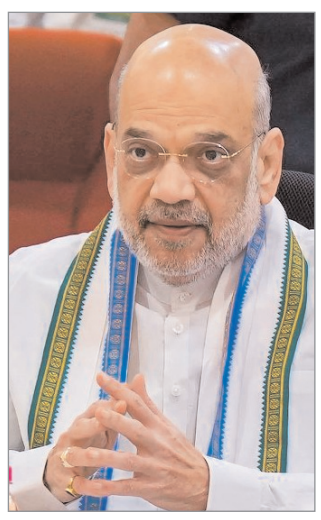

राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम पहलू- नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि तकनीक मानव जीवन के लिए आशीर्वाद है लेकिन तकनीक के बढ़ते उपयोग से कई खतरे भी पैदा हो रहे हैं , इसीलिए साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम पहलू भी बन गई है। उन्होंने कहा कि इसलिए साइबर सुरक्षा के बिना किसी भी देश का विकास असंभव है।

साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर का होगा गठन- शाह ने इस समारोह में विभिन्न बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के गठन की भी घोषणा की। गृह मंत्री ने कहा कि ये सभी एजेंसियां ??ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और बिना किसी रुकावट के मिलकर काम करेंगी।

सटीक रणनीति बनानी होगी- शाह ने कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सटीक रणनीति बनानी होगी और एक ही दिशा में एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों के गठन से अच्छे परिणाम मिले हैं और साइबरदोस्त पहल के तहत विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी इंदौर उज्जैन 6 लेन का भूमिपूजन

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर/भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में 'स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान' आरंभ किया जाएगा। स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता के विचार पर केंद्रित इस अभियान के अंतर्गत जन-जन को स्वच्छता अपने व्यवहार में आत्मसात करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सभी स्तर पर गतिविधियां संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए अभियान में लोगों को श्रमदान तथा अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को भोपाल में कैबिनेट बैठक से पहले अनौपचारिक चर्चा में यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर को आरंभ होने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 के शुभारंभ अवसर पर सभी मंत्रीअपने-अपने प्रभार के जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हों तथा स्थानीय स्तर पर परिस्थिति अनुसार नवाचार करते हुए अभियान को प्रभावी बनाएं। उन्होंने बताया कि 17 सितम्बर को ही जनऔषधि केंद्रों का भी शुभारंभ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 18 व 19 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उज्जैन व इंदौर पधार रही हैं। राष्ट्रपति उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन रोड का भूमिपूजन करने के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होंगी।

जिलों को लेकर सुझाव प्राप्त करें मंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों की भौगोलिक सीमाओं की विसंगतियों और उनके कारण जनसामान्य को आने वाले कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्री अपने-अपने क्षेत्र तथा प्रभार के जिलों की कठिनाइयों को चिन्हित करें तथा इस संबंध में लोगों के सुझाव भी प्राप्त करें। जनसामान्य की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव, परिसीमन आयोग के सदस्य पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव को भेंजे जाएं।

स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तीन स्तंभ

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर से आरंभ होने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पर कैबिनेट की बैठक से पहले प्रस्तुतिकरण दिया गया।

जिसमें बताया गया कि अभियान के तीन प्रमुख स्तंभ हैं, प्रथम स्तंभ स्वच्छता की भागीदारी के अंतर्गत जनभागीदारी-जागरूकता और एडवोकेसी, द्वितीय स्तंभ सम्पूर्ण स्वच्छता के अंतर्गत श्रमदान व लक्षित इकाइयों के कायाकल्प और तृतीय स्तंभ सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। स्वच्छता की भागीदारी के अंतर्गत मंचीय कार्यक्रम, कार्यशाला, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और सहभागिता गतिविधियां की जाएंगी। सम्पूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता लक्षित इकाइयों के तहत वृहद स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट पृथककरण और प्रबंधन, स्वच्छता सुविधा उन्नयन, स्वयं-सेवकों के मोबेलाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ सम्मान एवं पुरस्कार के माध्यम से स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों में सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा सामग्री वितरण, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता-सत्र आयोजित होंगे।

इस तरह संचालित होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान

स्वच्छता ही सेवा अभियान में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित करने और इसे जनता का अभियान बनाने के लिए सोशल मीडिया, रेडिया, टीवी, समाचार पत्रों सहित सभी प्रचार माध्यमों से संदेशों का प्रसारण किया जाएगा। जिला, जनपद, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में पंचायत और नगरीयनिकाय के जन-प्रतिनिधि भाग लेंगे। स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, पर्यटन व संस्कृति तथा वन विभाग को विशेष दायित्व सौंपे गए हैं।

एमजी रोड थाने से 400 मीटर दूरी पर हुई घटना

युवक ने एसआई को पीटा-घसीटा गिराया और वर्दी भी फाड़ी

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। इंदौर में रामबाग ब्रिज चौराहे के पास एक शराबी उत्पात मचा रहा था। ट्रैफिक पुलिस के एसआई और जवान उसे रोकने गए तो युवक उनसे भी हाथा-पाई करने लगा और एसआई की वर्दी फाड़ दी। युवक की शिकायत एमजी रोड थाने पर की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मंगलवार की है। चौराहे पर एसआई नाथूराम दोहरे और दो आरक्षक ड्यूटी दे रहे थे। एक युवक चौराहे पर आया। वह नशे में धुत था। वह वाहनों को रोकने लगा। वह ऊटपटांग हरकतें करते लगा। इससे यातायात बाधित होने लगा तो एसआई दोहरे युवक को समझाने पहुंचे। युवक उनसे हुज्जत करने लगा। एसआई ने जोर से उसे धक्का दिया। इसके बाद युवक भी तैश में आ गया। उसने एसआई की वर्दी पकड़ ली और झूमाझटकी करने लगा। इस बीच युवक का एक और साथी आ गया और उसने भी हुज्जत शुरू कर दी। चौराहे पर तैनात दो ट्रैफिक जवान भी आए और मामला शांत कराया। युवक पर तीन पुलिसकर्मी भी काबू नहीं कर सके। जोर-जोर से चिल्लाते हुए आरोपी एसआई की वर्दी खींच रहा था। उसने एसआई को धक्का भी दे दिया। एसआई की उम्र अधिक है, इसलिए युवक उन पर हावी हो रहा था। गिरने के कारण एसआई की वर्दी फट गई और बटन भी टूट गए। युवक को दूसरे ट्रैफिक जवानों ने राहगिरों की मदद से पकड़ा। यह घटना एमजी रोड थाने से 400 मीटर दूरी पर हुई। जब रवि एसआई की कॉलर पकड़कर घसीट रहा था, तब दोनों आरक्षक

अतुल और आशीष ने बीच-बचाव किया, लेकिन एसआई को छुड़ा नहीं पाए। रवि ने एसआई को जमीन पर पटक दिया। दूसरा युवक रवि को एसआई से दूर ले गया। वहां मौजूद राहगीर पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते रहे। इसके बाद एसआई ने एमजी रोड थाने में रवि के खिलाफ शिकायत की। एसआई दौहरे इसी साल रिटायर होने वाले हैं।

कई मामलों में शामिल रहा है आरोपी

पुलिस के मुताबिक, रवि पहले भी कुछ कई मामलों में शामिल रहा है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए रवि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। जनता के साथ पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

यह बताया एडिशनल डीसीपी ने

एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि मंगलवार सुबह नगर निगम चौराहे पर एसआई नाथूराम दौहरे (62) ट्रैफिक संभाल रहे थे। उनके साथ दो आरक्षक आशीष और अतुल भी तैनात थे। आरोपी रवि कश्यप का ई-रिक्शा चालक से विवाद हुआ था। दोनों को झगड़ते देख चौराहे पर जाम लगने लगा। एसआई दौहरे युवकों को शांत कराने पहुंचे। रवि नशे में था। उसने एसआई की वर्दी की कॉलर पकड़ ली। दूसरा युवक एसआई को बचाने लगा। लेकिन रवि ने एसआई को नहीं छोड़ा। उसने एसआई को जमीन पर पटक दिया। झूमाझटकी में एसआई का मोबाइल और वॉकी-टॉकी गिर गया। वर्दी फट गई और बटन भी टूट गए।

वारदात कर गुना भागे और करने लगे वार्ड उपचुनाव का प्रचार

बीबीए की छात्रा को छेड़ने वाले निकले भाजपा के 'चुनाव प्रचारक'

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। इंदौर में छेड़छाड़ के आरोपियों को पुलिस ने भंवरकुआं के उसी इलाके में जुलूस निकाला, जहां उन्होंने छात्रा से छेड़छाड़ की थी। आरोपियों ने महिलाओं के सम्मान में नारे भी लगवाए। पुलिस ने पहले छात्रा की शिकायत नहीं सुनी थी, लेकिन मीडिया में जानकारी लगने के बाद एफआईआर दर्ज कर टीमें बनाकर आरोपियों को पकड़ा गया। टीआई राजकुमार यादव और उनकी टीम ने मंगलवार को मंजीत रघुवंशी, संदीप सोलंकी, रवि नरवरिया, संजय रघुवंशी उर्फ बग्गा, सौरभ रघुवंशी और शुभम शर्मा उर्फ पण्डा का जुलूस निकाला। सभी आरोपी गुना के रहने वाले हैं और आदतन अपराधी हैं। उन पर हत्या का प्रयास, बलवा, चाकूबाजी, अड़ीबाजी, रास्ता रोक पीटना, तोड़फोड़, हथियार रखना, अवैध शराब, अपहरण कर दुष्कर्म करना, घरों में घुसना, तोड़फोड़, सट्टा खेलना व खिलवाना जैसे छह अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को इलाके में घुमाने के बाद गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई। तीन आरोपी जिलाबदर की सजा काट रहे हैं। एक आरोपी ने तो गुना में भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ पार्टी का प्रचार करते हुए फोटो खिंचवाया था।

शुक्रवार को हुई थी छेड़छाड़ की घटना

छेड़छाड़ की यह घटना शुक्रवार को हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सोमवार को भोपाल से आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी छात्रा को अगवा कर ले जाना चाहते थे। छात्रा के साथी ने सतर्कता से आरोपियों की कार का फोटो खींच लिया था, जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। घटना के दौरान लड़की के साथी ने पुलिस को फोन लगाया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। आखिर में दोस्तों को बुलाया तो बदमाश भागे।

वारदात के बाद गुना भागे और करने लगे भाजपा का प्रचार

वारदात करने के बाद कुछ बदमाश गुना भाग आए। इनमें से एक जिलाबदर बदमाश संदीप सोलंकी नगरपालिका के वार्ड 30 के उपचुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करता तक दिखा। इस दौरान कई फोटो भी सामने आए हैं। खुद संदीप सोलंकी ने भी सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर किए हैं। आरोपियों में से एक राहुल नरवरिया इंदौर में रहता है, उसी ने इन्हें यहां बुलवा लिया था। पुलिस ने सबसे पहले राहुल को पकड़ा और फिर उसी ने सबके नाम पते बताए। दीनदयाल पार्क के पास शुक्रवार रात सभी बदमाश स्कार्पियो में शराब पी रहे थे। 12.30 बजे घर लौट रही बीबीए की छात्रा को बदमाशों ने रोका और उसे बैडटच करने लगे। उसके साथी ने पुलिस को फोन लगाया लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। आखिर में दोस्तों को बुलाया तो बदमाश भागे। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि वारदात करने के बाद गुना में भाजपा का प्रचार करने में लग गए। नगरपालिका के वार्ड 30 के उपचुनाव में एक जिलाबदर बदमाश संदीप सोलंकी भाजपा के लिए प्रचार करता रहा। संदीप पर 21 मुकदमे दर्ज हैं। संदीप सोलंकी ने खुद भी सोशल मीडिया पर इसके फोटो शेयर किए हैं। इनमें वह भाजपा का दुपट्टा पहने हुए दिख रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार भी उसके साथ बैठे नजर आ रहे हैं।

डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कोर्ट ने लिया संज्ञान, नगर निगम को नोटिस

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। नगर निगमों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। इंदौर में अब तक डेंगू के 300 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं।

मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ ने एक जनहित याचिका में सुनवाई की। याचिका आरटीआई कार्यकर्ता विजय बजाज ने लगाई है। कोर्ट ने उनके वकील आदित्य सांघी की दलीलें सुनीं।

आरोप है कि पूरे मप्र में डेंगू फैल रहा है और हर दिन मरीज बढ़ रहे हैं और 10 सितंबर को ही सरकारी और प्राइवेट

मेडिकल अस्पताल खचाखच भर गए हैं। इस बार डेंगू वायरस के मजबूत संस्करण के कारण मौतें बढ़ रही हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अदालत ने नोटिस जारी किया और मध्य प्रदेश के नगर निगमों की कार्रवाई और जवाब के इंतजार में ठीक 10 दिनों के बाद मामले को 19 सितंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।

आरोप यह है कि संबंधित शहरों के सांसद भी इस मामले में ध्यान नहीं दे रहे हैं और पूरे मप्र में फॉगिंग मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि उचित कीटनाशक के साथ फॉगिंग मशीनों का उपयोग किया जाए और स्वच्छता बनाए रखी जाए तो डेंगू वायरस को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार के कारण जनता त्रस्त है और हर दिन डेंगू से लोगों की मौत हो रही है, जो इस साल जानलेवा साबित हो रहा है और मप्र में युवाओं की मौत की खबरें आ रही हैं।

खजूरी बाजार से अतिक्रमण हटाने पर व्यापारियों और निगम टीम में विवाद

इंदौर। इंदौर के खजूरी बाजार इलाके में मंगलवार सुबह नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान व्यापारियों और निगम टीम के बीच विवाद की स्थिति बन गई। दरअसल, अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकी के लिए नगर निगम रास्ते के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम के अमले ने खजूरी बाजार सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर जेसीबी से खाली पड़े प्लॉट से कबाड़ का सामान हटा दिया। हालांकि, कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन निगम ने सख्ती से कार्रवाई पूरी कर दी। नगर निगम जोन 20 की भवन अधिकारी पल्लवी पाल ने बताया कि अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह निकलेगा, जबकि खजूरी बाजार का यह जर्जर भवन खतरनाक हो चुका था। इसके चलते निगम के रिमूवल अमले ने सुबह खजूरी बाजार स्थित गोपाल रावत के मकान नंबर 620 पेन वर्ल्ड के खिलाफ कार्रवाई कर उसे जमींदोज किया। पल्लवी पाल ने बताया कि इसे तोड़ने के लिए कई ई-नोटिस नोटिस दिए गए, लेकिन मालिक ने उसे तोड़ने की कार्रवाई नहीं की। इसके चलते मंगलवार को निगम के रिमूवल अमले ने जर्जर मकान का हिस्सा तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान दुकानदार व महिलाओं ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी से से किसी का विरोध कारगर नहीं हो सका।

इंदौर में 13 से 15 सितंबर तक होगी आरएसएस की अहम बैठक

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों की तीन दिनी बैठक इंदौर में 13 सितंबर से होने जा रही है। इसमें 200 पदाधिकारी शामिल होंगे और संगठनों की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तय करेंगे। अगले साल आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीते दो साल से संघ के अनुषांगिक संगठनों ने कई गतिविधियां देशभर में संचालित कीं। अयोध्या में राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में माहौल बना। आरएसएस से जुड़े संगठनों ने इसके लिए कई आयोजन किए। अगले साल भी संघ इन संगठनों की माध्यम से सामाजिक गतिविधियों में ज्यादा हिस्सेदारी करेगा। इसकी रणनीति समन्वय बैठक में बनेगी। लोकसभा चुनाव के बाद समन्वय विभाग की अखिल भारतीय स्तर की यह पहली बैठक है। बैठक में केंद्रीय स्तर के कुछ पदाधिकारी शामिल होंगे, जबकि देशभर से 200 से ज्यादा पदाधिकारी आएंगे। भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। पांच साल पहले भी यह बैठक बायपास के एक गार्डन में हुई थी। इस बार यह बैठक बायपास स्थित अग्रसेन भवन में होगी।

आरएसएस अपने स्थापना के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रहा है। संघ मालवा प्रांत में सबसे मजबूत है। वर्षगांठ के मौके पर इंदौर में राऊ स्थित स्कूल में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो सकते हैं। संघ इस साल भी सामाजिक समरसता और समाजों में पैठ बनाने पर फोकस करेगा, ताकि समाज के लोग संघ की विचारधारा से जुड़ सकें।

200 पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संघ के इस दक्षता कार्यक्रम में जिन 200 पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा, सिर्फ वहीं इस बैठक में शामिल होंगे। अन्य संगठन के किसी भी पदाधिकारी या नेता को इस कार्यक्रम में एंट्री नहीं मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि एक बार जो पदाधिकारी 13 सितंबर को बैठक में शामिल होने के लिए अंदर जाएंगे, वह फिर बैठक खत्म होने के बाद यानी 15 सितंबर को ही बाहर निकलेंगे। इस दौरान उनकी जरूरत का सभी सामान अग्रसेन भवन में ही उपलब्ध रहेगा।

11 माह पहले भी हुई थी बैठक

इंदौर में 11 महीने पहले यानी विधानसभा चुनाव के पहले समन्वय बैठक हुई थी। लेकिन वह बैठक 13 से 15 सितंबर को होने वाली बैठक से बहुत अलग थी। इस एक दिवसीय बैठक में चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। 11 महीने पहले हुई बैठक में संघ के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार के अलावा मध्य क्षेत्र प्रचारक दीपक विस्पुते, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शामिल हुए थे।

सुबह से शाम तक चली बैठक में मुख्य रूप से चुनाव के दौरान समन्वय और कार्य रचना पर बात हुई थी।

हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ाई तारीख

हज यात्रा के लिए अब 23 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को 23 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। इंदौर जिला हज कमेटी के अध्यक्ष राशिद शेख ने बताया यह निर्णय राज्य हज समितियों, हज से जुड़े सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, पासपोर्ट कार्यालयों की छुट्टियों और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते प्रभावित जनजीवन को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही हज के इच्छुक यात्रियों के बढ़ते अनुरोधों को भी ध्यान में रखा गया है। जिला हज कमेटी इंदौर के जिला अध्यक्ष राशिद शेख ने बताया कि हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग अब 23 सितंबर 2024 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल ऐप हज सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला अध्यक्ष राशिद शेख ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे हज 2025 की गाइड लाइंस और शपथ पत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह तारीख

लगभग अंतिम है और इसके बाद विस्तार असंभव है, क्योंकि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों के अनुसार हज 2025 के सभी प्रशासनिक कार्य अक्टूबर तक पूरे करने होंगे। इसलिए इच्छुक आवेदकों से गुजारिश की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन अवश्य जमा कर दें। उन्होंने कहा कि किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य हज समितियों के कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। हज कमेटी के हेल्पलाइन नंबर 022-22107070 पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

इसलिए बढ़ाना पड़ी तारीख

प्रदेशभर से मिलने वाले इतनी बड़ी तादाद में आवेदन का असर यह भी होता रहा है कि एमपी को मिलने वाले सीमित हज कोटे की वजह से चाहतमंदों को निराश होना पड़ता था। गौरतलब है कि हज 2025 के आवेदनों की कम संख्या वाले हालात सिर्फ मप्र से ही नहीं हैं, बल्कि यह स्थिति पूरे में बनी हुई है। इसको देखते हुए सेंट्रल हज कमेटी ने हज आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ाकर अब 23 सितंबर कर दी है।

नई हज पॉलिसी का असर

हज 2025 के लिए घोषित की गई पॉलिसी में हज नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। इसके अनुसार हज कमेटी को मिलने वाले कोटे में कटौती की गई है। साथ ही प्राइवेट कोटे को बढ़ा दिया गया है। हजयात्रियों को उम्र सीमा में बांधने और पति पत्नी को एकसाथ ठहरने पर पाबंदी जैसे हालात भी नई पॉलिसी से बने हुए हैं।

कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रही मप्र राज्य हज कमेटी सचिव

मप्र राज्य हज कमेटी सचिव फरजाना गजाल के पास कमेटी का अतिरिक्त प्रभार है। वे मूल रूप से मप्र वक्फ बोर्ड की सीईओ हैं। जिसके चलते वे हज कमेटी के कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रही हैं। जरूरतमंद हज चाहतमंद लोगों से मिलने, उन्हें सहयोग या मार्गदर्शन देने में न उनकी रुचि है और न ही वे इसके लिए समय ही निकाल पाती हैं। हज यात्रा से पहले प्रदेश से जाने वाले हाजियों के सऊदी अरब में ठहरने की जगह के चयन प्रक्रिया पूरी करने पहुंचना भी फरजाना गजाल के लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसका असर यह होगा कि सऊदी सरकार द्वारा जारी की जाने बिल्डिंगों पर ही प्रदेश के हाजियों को गुजारा करने की मजबूरी रहेगी।

दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा

अगले सत्र से विद्यार्थियों को निःशुल्क उपाधि देगा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय

सिटी चीफ भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगले सत्र से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय सभी पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से उनकी उपाधि प्रदान करेगा। मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने समारोह के दौरान दीक्षित सभी विद्यार्थियों के साथ ही बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह कार्यक्रम में एक बड़ा बयान देते हुए बताया कि किस तरह से पहले के विद्वानों द्वारा गलत तरीके से इतिहास को प्रस्तुत करके हमारे देश के विद्यार्थियों को हमारे

पूर्वजों के महान कार्यों, उनके गौरव और सम्मान से हमें दूर रखा गया है और इतिहास से भ्रमित किया गया है।

वास्कोडिगामा के जहाज से कई गुना बड़ा था गुजरात के व्यापारी का जहाज

मंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाया गया कि भारत की खोज वास्कोडिगामा ने की थी जबकि हकीकत यह है कि गुजरात के एक व्यापारी जिनका नाम चंदन था वह जहाज से उस टापू पर गए थे जहां वास्कोडिगामा मौजूद था और वास्कोडिगामा ने उनसे भारत देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर चंदन नाम के व्यापारी ने वास्कोडिगामा को अपने जहाज के पीछे उसका जहाज लाने की बात कही और इस प्रकार वास्कोडिगामा ने भारत को देखा। गुजरात के व्यापारी चंदन का जहाज वास्कोडिगामा के जहाज से कई गुना बड़ा था।

गौरव और सम्मान को वापस लाने का प्रयास

उच्च शिक्षा मंत्री ने दूसरा उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे ही कोलंबस के बारे में भी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। परमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा में अब ऐसे भ्रम को दूर करने के हर स्तर पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के गौरव और सम्मान को जिन लोगों ने दबाकर रखा था और हम तक पहुंचने में रुकावट उत्पन्न की थी अब उस गौरव और सम्मान को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है और उन गलतियां को हर स्तर पर दूर करने की कोशिश की जा रही है। दीक्षांत समारोह में कुल 94 शोधार्थियों को एचडी की उपाधि के साथ ही एक डीएससी उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर में डिग्रियां प्रदान की गई है। दीक्षांत समारोह के दौरान 28 विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियां के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है।

स्वस्तिवाचन के साथ किया प्रवेश

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की शोभा यात्रा ने स्वस्तिवाचन के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रवेश किया। फिर राज्यपाल व कुलाधिपति मंगुभाई पटेल से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन ने अनुमति प्राप्त कर दीक्षांत समारोह की प्रक्रिया आरंभ की। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर जैन ने विद्यार्थियों को दिए उपदेश में शपथ का वाचन कराया। शपथ के अंतर्गत तैतरेय उपनिषद के 11 वें अनुच्छेद से लिए गए अंश का संस्कृत में विद्यार्थियों से वाचन कराया गया। कार्यक्रम शुरू होने के पहले राज्यपाल मंगु भाई पटेल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मंच परआने के बाद पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान जन मन गण की धुन प्रस्तुत की गई।

रीवा एयरपोर्ट को मिला डीजीसीए का लाइसेंस

सीएम बोले-विकसित मध्य प्रदेश की ओर एक और कदम

सिटी चीफ भोपाल।

विंध्य क्षेत्र में स्थित रीवा एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से यात्री और मालवाहक उड़ानों के संचालन के लिए आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त हो गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश के आर्थिक और पर्यटन विकास को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ह्यविकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेशह्न अभियान के अंतर्गत यह एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

एयरपोर्ट से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में होगा सुधार

रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए उड़ानों के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से सीधा संपर्क स्थापित होगा। इसके अतिरिक्त, इस एयरपोर्ट से क्षेत्र के विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे रीवा के किले, गोविंदगढ़ और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंच

आसान होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रीवा एयरपोर्ट का परिचालन शुरू होने से क्षेत्र में व्यापार और निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मालवाहक उड़ानों के संचालन से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी, जिससे व्यापार का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए से लाइसेंस मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद देते हुए कहा कि एयरपोर्ट प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी और व्यापारिक संभावनाओं को नया आयाम देगा। रीवा एयरपोर्ट के चालू होने से प्रदेश का विंध्य क्षेत्र न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।

उचित मूल्य पर उपलब्धता के लिए सरकार ने निर्धारित की भंडारण की अधिकतम सीमा

3 हजार टन से अधिक गेहूं के स्टॉक पर प्रतिबंध

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। गेहूं की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। अब थोक व्यापारी तीन हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए यह सीमा दस टन निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक के लिए बनाई गई है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारण की अधिसूचना जारी की

है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टाक सीमा एवं स्टाक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 जारी किया है।

31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा नियम

इसमें थोक और फुटकर व्यापारी के साथ प्रोसेसर के लिए अधिकतम भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी है। प्रोसेसर मासिक क्षमता के 70 प्रतिशत मात्रा को वर्ष 2024-25 के शेष माह से हिसाब से रख सकता है।

सभी को भंडारण सीमा की घोषणा करनी पड़ेगी। जब भी जांच के लिए दस्तावेज मांगे जाएं या भौतिक सत्यापन किया जाए तो इसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी को रहेगी।

शहडोल, मुरैना व नर्मदापुरम में 2026 तक ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की इकाई प्रारंभ करने की तैयारी

भोपाल। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) और विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के तीन नए संभागीय कार्यालय वर्ष 2026 के अंत तक शुरू करने की तैयारी है। शहडोल, मुरैना और नर्मदापुरम में यह कार्यालय खोले जाएंगे।

तीनों जगह बनाए जाने वाले भवन में आरोपितों को रात में रखकर पूछताछ की व्यवस्था भी रहेगी। यह कार्यालय खुलने का सबसे बड़ा लाभ शिकायतकताओं को मिलेगा। अभी उन्हें सौ से डेढ़ सौ किमी तक चलकर शिकायत या बयान दर्ज कराने के लिए जाना पड़ता है।

उदाहरण के रूप में शहडोल के शिकायतकर्ता को रीवा, नर्मदापुरम वाले को भोपाल आना पड़ता है। पुलिस को भी ट्रेपिंग में आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही काम बंटने से शिकायतों की जांच और अभियोजन में तेजी आएगी।

अभी शिकायत दर्ज होने के बाद डेढ़ से दो वर्ष जांच के बाद प्राथमिकी (पीई) दर्ज हो पा रही है। प्रदेश में

ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पुलिस की अभी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और सागर में इकाई हैं।

शिकायतों की जांच और अभियोजन में लोकायुक्त पुलिस से अधिक समय ईओडब्ल्यू में लग रहा है। कारण यह कि ईओडब्ल्यू में स्वीकृत अधिकारी-कर्मचारियों की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत ही कार्यरत हैं।

सरकार ने दी अनुमति, भ्रष्टाचार करने पर ईओडब्ल्यू ने 2013 में दर्ज किया था प्रकरण

जल संसाधन विभाग के पूर्व अफसरों के खिलाफ 11 साल बाद चलेगा केस

सिटी चीफ भोपाल।

डिंडोरी के हंसापुर और रीवा में जलाशय निर्माण के करोड़ों रुपये के टेंडर में भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता मदन गोपाल चौबे (एमजी चौबे) और कार्यपालन अधिकारी शिखर जैन के खिलाफ अब मुकदमा चलाया जाएगा। करोड़ों के टेंडर में फजीवाड़ा कर गबन करने पर मप्र आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने 2013 में प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन विभाग ने कोर्ट में केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं दी थी। अब दोनों अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 11 वर्ष बाद जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। डॉ. राजौरा के निर्देश पर उप सचिव आशीष तिवारी के हस्ताक्षर से दोनों पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अब कोर्ट में केस चलाने की अनुमति मिल गई है।

सरकारी योजनाओं में किया था भ्रष्टाचार

जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए एमजी चौबे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया था। शिखरचंद जैन रिटायर्ड एसडीओ कुंडम सब डिवीजन-3 और प्रभारी कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर भी आरोपी बनाए गए हैं। प्रमुख अभियंता चौबे इस दौरान तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिंडोरी पदस्थ थे। ईओडब्ल्यू द्वारा 2013 में प्रकरण दर्ज करने के बाद अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई थी, लेकिन विभाग ने स्वीकृति नहीं प्रदान की। विभाग ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं देते हुए कहा था कि ठेकेदार संतोष कुमार मिश्रा के टेंडर के मामले में हुई गड़बड़ी पर पूर्व एसडीओ जैन और पूर्व कार्यपालन यंत्री जिम्मेदार नहीं हैं। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना और उसका सत्यापन करना टेंडर प्रक्रिया का एक शुरूआती पार्ट है। इसे आधार बनाकर ईओडब्ल्यू द्वारा इन अफसरों को वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार बताया गया है। यह उचित प्रतीत नहीं होता है। हंसा जलाशय और रीवा जलाशय के ठेके के काम के मामले में फर्जी और कूटरचित दस्तावेज बनान में इन अफसरों की भूमिका को लेकर अभियोजन स्वीकृति नहीं दी थी।

सम्पादकीय

दिव्यांग खिलाड़ी देश के 'महानायक' क्यों नहीं?

दिव्यांग खिलाड़ी देश के 'महानायक' क्यों नहीं हैं? वे भी 'तिरंगाधारक'और 'जन गन मन...' की वैश्विक गूंज हैं। वे ओलंपिक पदकवीरों की तरह लोकप्रिय और राष्ट्रीय सम्मान के पात्र क्यों नहीं हैं? उनकी सार्वजनिक पहचान ऐसी क्यों नहीं है कि उन्हें भी 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे लोकप्रिय मंचों पर आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए? कमोबेश देश देखे कि किन योद्धाओं ने विकलांगता से लड़ कर अंतरराष्ट्रीय गौरव हासिल किया है और भारत के मस्तक पर तिलक किया है! भारत दिव्यांग-मैत्री वाला देश नहीं है। यहां के सार्वजनिक जीवन में दिव्यांगों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा बहुत कम है।

पेरिस पैरालंपिक खेल महाकुंभ, 2024 भी सम्पन्न हुआ, लेकिन भारत के लिए यादगार बन गया। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने कीर्तिमानों, उपलब्धियों और पदकों के अभूतपूर्व अध्याय रच दिए। 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 19 पदक हासिल किए थे, लेकिन इस बार 10 अधिक पदक जीते हैं। ये खिलाड़ी सामान्य प्राणी नहीं हैं। वे दिव्यांग हैं, आधे-अधूरे और असहाय हैं, लेकिन उनके भीतर करिश्मों वाला कोई फरिश्ता मौजूद है। विकलांग होने के बावजूद उन्होंने दिव्यता के साथ सफलताएं अर्जित की हैं, नतीजतन भारत पहली बार 20 शीर्ष देशों की जमात में शामिल हुआ है। पेरिस पैरालंपिक में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदक, यानी कुल 29 पदक जीत कर 18वें स्थान पर रहा है। चुनौतियां और मुकाबले पैरा खिलाड़ियों के लिए भी उतने ही कांटेदार थे, जितने सामान्य अंगी, सशक्त, मजबूत ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए थे, लेकिन ओलंपिक में झोली 'स्वर्णहीन' रही, एक रजत और 5 कांस्य, यानी कुल 6 पदक ही हम जीत सके और 71वें स्थान पर रहे। हमने उस प्रदर्शन का भी अभिनंदन किया और देशभर में खिलाड़ियों के सम्मान किए गए। करोड़ों के इनाम घोषित किए गए। भारत ने अपने खिलाड़ियों को सिर-आंखों पर बिठाना सीख लिया है। हालांकि सफलता, उपलब्धियों और राष्ट्रीय सम्मान की आपसी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन पैरालंपिक में निशानेबाज अवनी लेखरा और भाला फेंक में सुमित अंतिल की दोहरी स्वर्णिम उपलब्धि को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? दोनों टोक्यो पैरालंपिक के चैम्पियन थे और इस बार भी चैम्पियन बने हैं। सुमित ने 70.59 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। वह नीरज चोपड़ा का ही संस्करण लगता है। इसी श्रेणी में तीरंदाजी में हरविन्दर सिंह, बैडमिंटन में नितेश कुमार, ऊंची कूद में प्रवीण कुमार, क्लब थ्रो में धर्मबीर और छोटे कद वाले, भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप सिंह ने स्वर्णिम सफलताएं हासिल कर सोचने को बाध्य कर दिया है कि ये दिव्यांग खिलाड़ी देश के 'महानायक' क्यों नहीं हैं? वे भी 'तिरंगाधारक'और 'जन गन मन...' की वैश्विक गूंज हैं। वे ओलंपिक पदकवीरों की तरह लोकप्रिय और राष्ट्रीय सम्मान के पात्र क्यों नहीं हैं? उनकी सार्वजनिक पहचान ऐसी क्यों नहीं है कि उन्हें भी 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे लोकप्रिय मंचों पर आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए? कमोबेश देश देखे कि किन योद्धाओं ने विकलांगता से लड़ कर अंतरराष्ट्रीय गौरव हासिल किया है और भारत के मस्तक पर तिलक किया है! भारत दिव्यांग-मैत्री वाला देश नहीं है। यहां के सार्वजनिक जीवन में दिव्यांगों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा बहुत कम है। 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार वाला कानून' 2016 में पारित किया जा चुका है। उसमें विशेष प्रावधान था कि पांच वर्षों में सार्वजनिक स्थलों को दिव्यांग-मित्र बनाया जाए, लेकिन इसका क्रियान्वयन संतुष्टि से कोसों दूर है। केंद्र सरकार ने बजट भी कम कर दिया है। हैरत है कि निजी भवन और परिवहन प्रणाली, महानगरों और मेट्रों शहरों में भी, इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। पैरा खिलाड़ियों ने इस व्यवस्था को भी सबक सिखाने का काम किया है। 2016 में हमने पैरालंपिक खेलों में शिरकत करना शुरू किया था। उससे पहले 2012 के लंदन और 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भारत को क्रमशः मात्र एक पदक और 3 पदक ही नसीब हुए थे। अत्यंत निराशापूर्ण और अपमानजनक दौर था। 2016 में पैरालंपिक में हमने 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते थे, लिहाजा उम्मीद की किरण दिखाई दी, तो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा खिलाड़ियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया और मुलाकात कर बहुत कुछ समझने की कोशिश की।

जम्मू-कश्मीर पर रक्षामंत्री का दूरगामी संदेश

विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुलाम कश्मीर पर अपना दावा कभी नही छोड़ेंगे। वैसे भी गुलाम कश्मीर के लोग हमारे ही लोग हैं, उन्हें पाकिस्तान ने कभी अपना माना ही नहीं है। राजनाथ सिंह का गुलाम कश्मीर के लोगों को संदेश पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील की तरह है।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार को एक नई करवट देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसी बातें कहीं है जो घाटी के लोगों के दिलों को छूने वाली होने के साथ प्रांत में नई उम्मीदों के नए दौर का आगाज है एवं गुलाम कश्मीर के लोगों के प्रति सहानुभूति एवं आत्मीयता दर्शाने वाली है। एक दिन पहले करगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो बात कुबूल कर ली, जो अब तक सारे पाकिस्तानी जनरल पूरी दुनिया से छिपाते रहे। आसिम मुनीर ने साफ-साफ कहा कि कारगिल जंग में पाकिस्तानी सेना का हाथ था। उनके सैनिकों ने शहादत दी है। इसके अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू-कश्मीर की धरती से यह ऐलान कि अगर पाकिस्तान आतंक छोड़ दे तो उसके साथ बातचीत हो सकती है। यह बयान बहुत कुछ कहता है एवं इसके कई दूरगामी राजनीतिक दृष्टिकोण है। पाकिस्तान समझ चुका है कि कश्मीर में अब उसका कुछ नहीं बचा। रही सही कसर, जम्मू-कश्मीर में हो रहे चुनावों में लोगों की जोरदार भागीदारी ने पूरी कर दी। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, ऐसे में वह हकीकत स्वीकार करता नजर आ रहा है। रक्षामंत्री की कही बातों में पाकिस्तान सरकार को सीधा संदेश दिया गया है। निश्चित ही राजनाथ सिंह के बयान एक अनुभवी एवं कद्दावर नेता के रणनीतिक एवं दूरगामी सोच से जुड़े बयान है, जिनकी प्रतिक्रिया दोनों ही देशों में होने के साथ ही चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट का बड़ा कारण बना है। कश्मीर में विकास, पर्यटन में भारी वृद्धि, शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनना गुलाम कश्मीर के लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि उन्हें भी इस ओर आजाद फिजा में सांस लेने का मौका मिले। ऐसे में रक्षामंत्री ने उन्हें भारत का हिस्सा बनने का निमंत्रण देकर पड़ोसी देश की दुखती रग को छेड़ दिया है एवं पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, बल्कि गुलाम कश्मीर के लोगों में भी नया विश्वास एवं मनोबल जगा दिया है। रक्षामंत्री का यह निमंत्रण बहुत मायने रखता है, इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि गुलाम कश्मीर हमारा है एवं हम इसे लेकर रहेंगे। गुलाम कश्मीर के लोग भारत से मिलने के लिए उत्सुक है, आंदोलनरत है। क्योंकि पाकिस्तानी शासक उन्हें विदेशियों की तरह देखते हैं। यह एक सच्चाई भी है।

पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का जैसा दमन और शोषण कर रहा है, उसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। इसी दमन और शोषण के चलते जब-तब वहां पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोग भारत जाने की अनुमति भी मांगते रहते हैं।

गुलाम कश्मीर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों को मारा जा रहा है। वहां के लोग यह अच्छी तरह देख रहे हैं कि भारतीय भूभाग में किस तरह तेजी से विकास हो रहा है और उन्हें किस तरह पाकिस्तान की ओर से ठगा जाता रहा है। कहना कठिन है कि रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तान क्या कहता है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि वह आतंकवाद को सहयोग-समर्थन देने से बाज आएगा। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे इस चुनाव पर सिर्फ भारतीयों नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुलाम कश्मीर पर अपना दावा कभी नही छोड़ेंगे। वैसे भी गुलाम कश्मीर के लोग हमारे ही लोग है, उन्हें पाकिस्तान ने कभी अपना माना ही नहीं है। राजनाथ सिंह का गुलाम कश्मीर के लोगों को संदेश पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील की तरह है।

रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य के जरिये चुनाव के परिदृश्यों को एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उनके लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता पाकिस्तानपरस्ती का परिचय देते हुए उससे बात करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे यह रेखांकित नहीं करते कि वार्ता के लिए उसे आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद-370 की वापसी का भी सपना दिखा रहे हैं। यह दिवास्वप्न के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अब इस विभाजनकारी और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद की वापसी संभव नहीं और इसीलिए रामबन में राजनाथ सिंह ने कहा, भाजपा ने डंके की चोट पर अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर में शांति और समृद्धि का रास्ता बनाया है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वह इस अनुच्छेद को वापस ला सके। ऐसा कहते हुए उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और अनुच्छेद-370 की वापसी के उसके वादे पर मौन धारण किए हुए है। पाकिस्तान एवं घाटी के विभिन्न राजनीतिक दल बार-बार अनुच्छेद 370 का जिक्र कर दुनिया के सामने यह गीत गाते रहे हैं कि 370 हटने से कश्मीर के लोग नाराज हैं। इस झूठ को खुलासा स्वयं कश्मीर की जनता ने लोकसभा चुनाव में वोटिंग के जरिये किया है।

घाटी में चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे हैं राजनीतिक दल पाकिस्तानी राग अलापते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इस वक्त अफजल को दी गयी फांसी के विवाद में घिर चुके हैं।

उन्होंने कह दिया कि अफजल को फांसी देना गलत था।

चूंकि अफजल संसद पर हमले का जिम्मेदार था, उसकी तरफदारी करके नेशनल कान्फ्रेंस स्पष्ट रूप से जता रही है कि वह आतंकवादियों से मिली हुई है या उनकी तरफदारी कर रही है और कांग्रेस उसकी साथी है। इन स्थितियों में कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में किए गए वादों से सहमत है? उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह उमर अब्दुल्ला के इस आकलन से सहमत है कि संसद पर हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कुछ हासिल नहीं हुआ? यह अलगाववाद और आतंकवाद के दौर की वापसी के समर्थकों की हमदर्दी हासिल करने वाला ही बयान है और इसीलिए राजनाथ सिंह ने उन पर कटाक्ष किया कि अफजल को फांसी न दी जाती तो क्या उसके गले में हार डाले जाते। यह विडंबना ही है कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर भी चुप्पी साधे है, जबकि उसे फांसी की सजा मनमोहन सिंह सरकार के समय ही दी गई थी। ऐसे में कश्मीर के लोगों को तय करना होगा कि वे देश प्रेमियों के साथ हैं या देशद्रोहियों के साथ? बहरहाल, धारा 370 हटने के बाद यहां पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में पचास प्रतिशत से ऊपर मतदान हुआ था जो अच्छा संकेत है। वर्ना इससे पहले तो तीस प्रतिशत मतदान को भी अच्छा समझा जाता रहा।

जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता के साथ गुलाम कश्मीर एवं अनुच्छेद 370 के मुद्दे व्यापक रूप से उभर कर सामने आयेंगे। इन चुनावों में मतदाता जहां ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा राज्य की एक करोड पच्चीस लाख जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकास एवं शांति की दिशा में। इन स्थितियों में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर की जनता को जागरूक किया है एवं मतदान के प्रति सतर्क होने के साथ अपना मतदान विवेक से करने का वातावरण निर्मित किया है।

वक्फ प्रशासन में सुधार राष्ट्रीय हित में

वक्फ कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक वर्ग में काफी चिंता है। वक्फ, मुसलमानों की एक प्रमुख प्रथा है, जिसमें धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति दान की जाती है। इस मुद्दे को मीडिया में व्यापक रूप से स्थान मिला है। हैरानी की बात है कि संशोधन की विषय-वस्तु मालूम होने के बावजूद जमीनी वास्तविकता की अनदेखी करके मात्र सैद्धांतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब जबकि वक्फ संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विचाराधीन है, यह जरूरी है कि इसका निष्पक्ष, बिना किसी डर और धारणाओं से प्रभावित हुए विश्लेषण किया जाए। सरकार और संसद को इस मामले में सहमति और परामर्श से ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि समुदाय के एक वर्ग में व्याप्त डर और आशंकाएं कम हो सकें।

यह पहली बार नहीं है कि वक्फ कानून में बदलाव किया जा रहा है। 1913 और 1930 में भी इसमें संशोधन किए गए थे, जबकि अधिक व्यापक परिवर्तन वक्फ अधिनियम-1995 और वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2013 के माध्यम से किए गए थे।

वर्तमान विधेयक के कई बदलावों की सिफारिश 2006 में सच्चर समिति की रिपोर्ट और मार्च 2008 में राज्यसभा में प्रस्तुत वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी की गई थी। इन सिफारिशों में वक्फ के प्रबंधन में सुधार के लिए विभिन्न उपाय शामिल थे, जैसे प्रबंधकों के कामकाज को विनियमित करना, अभिलेखों का कुशल प्रबंधन, वक्फ बोर्डों की संरचना का पुनर्गठन करते हुए अन्य सामाजिक समूहों को शामिल करना, तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय लेखा परीक्षा आदि। अतः यह कोई नया विचार नहीं है।

यह उल्लेख भी जरूरी है कि वक्फ में सुधार की मांग मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी उठ रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण और कुप्रबंधन जैसे मुद्दों पर मुसलमानों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती रही हैं, जो बड़े पैमाने पर मुकदमों के रूप में सामने आई हैं। इन शिकायतों के विश्लेषण में पाया गया कि अप्रैल 2023 से मिली 148 शिकायतों में से अधिकतर अतिक्रमण, वक्फ भूमि की अवैध बिक्री, सर्वेक्षण और पंजीकरण में अत्यधिक विलंब और वक्फ बोर्डों और प्रबंधकों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित थीं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के डाटा का विश्लेषण बताता है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक प्राप्त 566 शिकायतों में से 194 वक्फ भूमि पर अवैध अतिक्रमण और हस्तांतरण से संबंधित थीं और 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड के अधिकारियों व प्रबंधकों के खिलाफ थीं।

न्यायाधिकरणों में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ हैं। पिछले कई वर्षों में, तमाम सांसदों ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में देरी, वक्फ बोर्ड द्वारा बाजार मूल्य से कम किराया लेने, वक्फ भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, विधवाओं के विरासत अधिकार, सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण पूरा न करने, वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की धीमी प्रगति आदि के मुद्दे उठाए हैं।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि वक्फ बेशक धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई मुस्लिम संस्थाएं हैं, लेकिन वे सार्वजनिक संस्थाएं भी हैं, जिनमें राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है। इसलिए उनके प्रशासन में सुधार राष्ट्रीय हित में है। भारत के पास दुनिया की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। लगभग 8 लाख एकड़ वक्फ भूमि है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये है। यदि उनका पारदर्शी और कुशल उपयोग किया जाए, तो वे सभी समुदायों को लाभ पहुंचा सकते हैं। सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, ओमान, बांग्लादेश और तुर्किये जैसे देशों में वक्फ संपत्तियों को आम तौर पर सरकारी कानूनों और संस्थानों द्वारा विनियमित किया जाता है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वक्फ सुधारों पर बहस तर्कसंगत, वस्तुनिष्ठ और अनुभवों से प्रेरित होनी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव, जो सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाएं, का स्वागत होना चाहिए और यह मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक और कुशल प्रक्रिया की शुरुआत करने से प्रशासन में सुधार होगा। मुस्लिम समुदाय को भ्रामक सूचनाओं का शिकार नहीं होना चाहिए कि इन सुधारों से उनकी संपत्तियां छिन जाएंगी।

दो युद्ध और नैतिकता के तर्क

पहला युद्ध दो वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब आक्रमणकारी देश (रूस) ने महान युद्धों की तर्ज पर उनके एक छोटे संस्करण के रूप में सीमा पार अपने उस पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू किया, जिसके अस्तित्व को उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया। तबसे यूक्रेन ने न सिर्फ अपनी जमीन और लोगों को खोया है, बल्कि उसने साहस दिखाते हुए अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी हासिल किया है। यही नहीं, उसने आक्रमणकारी देश के इरादों को भी चकनाचूर कर दिया।

यूक्रेन ने रूस को आसानी से जीत हासिल करने की राष्ट्रवादी संतुष्टि से वंचित कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति अपनी युवकोचित सहजता और खुद को पीड़ित दर्शाने वाले भाव के साथ इस सदी के ऐसे स्वतंत्रता-सेनानी बन गए हैं, जो सबसे मदद की गुहार लगाते दिखते हैं। इस युद्ध के जल्दी खत्म होने के कोई लक्षण नहीं दिखते।

अब से करीब एक महीने बाद दक्षिणी इस्राइल में हमास द्वारा किए गए नरसंहार और बंधक बनाने की घटना को एक साल पूरे हो जाएंगे। गाजा एक ऐसे समूह के खिलाफ युद्ध का अपरिहार्य युद्धक्षेत्र बन गया है, जिसने गरीबी से त्रस्त इलाके की पूरी आबादी को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। इस युद्ध ने जो मानवीय संकट पैदा किया है, वह बहुत बड़ा है और आम फलस्तीनी उनके अधिकारों की कसम खाने वालों के पापों की कीमत जान देकर चुका रहे हैं।

ज्यादा प्रभावी सौदेबाज होने के नाते, हमास ने इस्राइली जनता की राय बदलने के लिए बंधकों के शवों को छोड़ दिया है और वह इसमें सफल भी हो रहा है। असल में हमास सैन्य शक्ति से युद्ध नहीं जीत सकता। इसलिए, वह दुनिया भर में प्रदर्शनों और उदारवादी संवेदनशीलता को प्रभावित करके, तथा वैश्विक जनमत में इस्राइल को अलग-थलग करके अपने द्वारा शुरू किए गए युद्ध को जीतने की उम्मीद कर रहा है।

हर युद्ध के बाद एक नैतिक संघर्ष होता है, जिसमें पीड़ित और हमलावर की छवि एक-दूसरे से बदल जाती है। यह सब देखने वालों के नैतिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यूक्रेन के मामले में नैतिकता अब भी विवाद का विषय है, क्योंकि उदारवादी जहां तानाशाहों के अतिरिक्त क्षेत्रीय आतंक के खिलाफ उग्र यूक्रेन की दृढ़ता की सराहना करते हैं, वहीं रूढ़िवादी इसे एक ऐसे देश की अनुचित वीरता बता कर खारिज करते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से रूस से जुड़ा रहा है। विवाद इसी नैतिकता से जुड़ा है। दुनिया के अधिकांश देशों के अनुसार, यूक्रेन की पीड़ा को उदार लोकतंत्र से जुड़े देशों द्वारा साझा किया जाना चाहिए। यूक्रेन उचित ही उदारवादियों के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि वह एक ऐसे शासन के खिलाफ खड़ा है, जिसके लिए राष्ट्रवाद और पुराने गौरव की शब्दावली में मौजूदा रक्तपिपासा न्यायोचित है और खोए हुए अतीत को बहाल करने की एक शर्त भी है।

कुछ रूढ़िवादियों का मानना है कि कीव को हथियार देने से मना करके और उसके नेता को पीड़ित होने का नाटक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच देने से रोक कर यूक्रेन युद्ध रोका जा सकता है। वे तर्क देते हैं कि विवेक को विचारधारा के अधीन नहीं किया जा सकता। आज की विभाजित नैतिकता में, पीड़ा को मापने के लिए अलग-अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। सड़कों के आक्रोश और क्रांतिकारी परिसरों से उभरने वाली कहानी में, जो उदारवादियों द्वारा वर्षों से सुनाई जा रही समान कहानी का ही एक संस्करण है, फलस्तीनियों की पीड़ा दिखती है, जिसे पिछले वर्ष सात अक्तूबर को हमास द्वारा किए गए नरसंहार ने एक अपरिहार्य भयावहता में बदल दिया। युद्ध की इस उदार आलोचना में, नेतन्याहू को बमबारी रोक देनी चाहिए, इससे पहले कि इस्राइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को काट दे, जो गाजा और मिस्र के बीच हमास की आपूर्ति लाइन है। बंधकों का शव के रूप में घर लौटना इस्राइल को युद्ध की निरर्थकता के बारे में अंतिम चेतावनी होनी चाहिए। लेकिन नैतिकता के इस तर्क में यह बात गायब है कि इस्राइल को भी राजनीतिक या रणनीतिक सुविधा से परे मृत बंधकों और अभी भी कैद में मौजूद दर्जनों लोगों के लिए आश्वासन मिलना चाहिए। असल में विभाजित नैतिकता में मानवता भी विवाद का विषय है।

उदारवादियों में पुतिनवाद को लेकर अब भी कोई आम सहमति नहीं है। रूस का नेता बेशक अब तक नेतन्याहू नहीं बन पाया है। लेकिन अगर पुतिनवाद पुरानी यादों पर आधारित नकली राष्ट्रवाद द्वारा कायम है, तो इसकी वजह यह है कि इसे रूस से परे उन वैचारिक ताकतों का समर्थन मिला है, जो अमेरिकी प्रभुत्व वाली दुनिया में प्रतिवाद की जरूरत महसूस करते हैं। यूक्रेन के लोगों की पीड़ा फलस्तीनी संघर्ष जितनी मार्मिक या विरोध-योग्य नहीं है, हालांकि पुतिन का रूस जिस सोवियत कल्पना से चिपका हुआ है, वह किसी भी उदारवादी तर्क से उस पैशाचिक ढंग से कम नहीं हो सकती है, जिसके सहारे वामपंथी इस्राइल की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं। फिर भी, वैचारिक सुविधावाद मिसाइलों के गिराने में भी नैतिकता ढूंढ सकता है। यह ऐसा है, जैसे पीड़ा की तीव्रता इस बात से निर्धारित होती है कि उदार विवेक पीड़ित को किस तरह से परिभाषित करता है। कुछ भी हो, इस्राइल जीत नहीं सकता। लेकिन, रूस मामूली चोटों को सह सकता है।

नैतिकता का विज्ञान ही ऐसा है, जो गाजा और यूक्रेन में युद्धों को समाप्त करने के आह्वान को असमान बनाता है। धारणा की लड़ाई हमास जीत रहा है, क्योंकि वे केवल सात अक्तूबर के अपराधी नहीं हैं, जो दावा करते हैं कि इस्राइल विस्थापन के इतिहास पर थोपा गया सबसे बड़ा झूठ है। इसके अतिरिक्त, उदारवादी यह नहीं देखते कि अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए युद्ध की स्थायी स्थिति में रहना इस्राइल की मजबूरी है। नैतिकता विचारधारा के अंतिम अवशेषों में फंसी हुई है, और दो युद्धों के हमारे अध्ययन से इसकी स्वतंत्रता स्थगित होती प्रतीत होती है।

27 सितम्बर को सागर में होगी रीजनल इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव

यह समिट उद्यमियों के लिये एक अच्छा

प्लेटफार्म साबित होगी-कलेक्टर

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले के उद्यमियों से कहा है बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आगामी 27 सितंबर को सागर में मुख्यमंत्री के मुख्य अतिथ्य में रीजनल इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव होने जा रही है, इस कॉन्क्लेव में देश-विदेश के अनेक बड़े उद्योगपति भाग लेने जा रहे हैं। यह कॉन्क्लेव चूकि बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रही है, तो यहाँ दमोह जिले में भी निवेश की नई संभावनाएं इससे बनने वाली हैं। औद्योगिक विकास और रोजगार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इसको माना जा सकता है।

कलेक्टर ने बताया इस कॉन्क्लेव में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। सभी उद्योगपतियों, उद्यमियों, स्टार्ट अप के संचालकों, युवा उद्यमियों, एफ़.पी.ओ. के संचालकों से और ऐसे स्वसहायता समूह जो की एक बड़े पैमाने पर उद्यमिता कर रहे हैं। उन्होंने कहा अधिक से अधिक संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और इस समिट में भाग लें। यह समिट ना केवल दमोह जिले में औद्योगिक विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी बल्कि सभी उद्यमियों के लिए भी एक बड़ा अच्छा प्लेटफार्म साबित होगी, उनको कई सारे नए एवेन्युस वहाँ पर पता चलेंगे और अलग-अलग तरह के उद्योगपतियों और अन्य सभी से मुलाकात होगी। वहां पर वायर सेलर मीट का आयोजन है, वहां पर कई सारी एग्ज़िबिशन लगेंगी, कई सारे सेशन्स होंगे, वन-टु-वन मीटिंग्स होंगी, तो यह हम सभी के लिये बहुत अच्छा प्लेटफार्म और बहुत अच्छा अवसर है, कि जिले में निवेश को अधिक से अधिक बढ़ा सके। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुये कहा सभी उद्यमी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, इसके लिए पोर्टल *invest.mp.gov.in* पर जाए, बहुत ही आसान सा रजिस्ट्रेशन है, अवश्य अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और दमोह जिले का अधिक से अधिक इसमें प्रतिनि

जनसुनवाई में 212 आवेदनों पर हुई सुनवाई

सारी व्यवस्थाओं का लगभग 200 लोगों ने लिया लाभ

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, जिले भर से आये नागरिकों ने अपनी समस्यायें जनसुनवाई में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष रखी, इस दौरान 212 आवेदनों पर सुनवाई करते हुये कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। आज की जनसुनवाई में कलेक्टर श्री कोचर ने अलग से 04 स्टॉल लगवाये जिनमें आधार अपडेट, मोबाइल से आधार लिंक,ई-केवाईसी, आयुष्मान कार्ड की सुविधा के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। इस अवसर पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया जनसुनवाई में 04 स्टॉल लगाए हैं, जिनका उद्देश्य यही था कि व्यक्ति यहां पर आता है, कम से कम दो से तीन घंटा वह यहां पर बिताता है, तो उसके कुछ दूसरे काम भी हो जाए, जिनके लिए उसको इधर-उधर भटकना न पड़े। आधार अपडेट के लिए यदि किसी को आधार अपडेट करना हो, मोबाइल से आधार लिंक करना हो इसकी सुविधा यहां पर दी है, ई-केवाईसी की सुविधा दी है, आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जिसमें बी.पी. शुगर जैसे बेसिक टेस्ट होते हैं इसके साथ कुछ बेसिक दवाइयां भी यहां पर रखवाई है और यहां पर डॉक्टर भी है। इस तरह से चार प्रकार के स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं, अभी तक इन सारी व्यवस्थाओं का लगभग 200 लोगों ने लाभ लिया है, जिसमें से 160 स्वास्थ्य परीक्षण हुये है, इसके अलावा लगभग 40 लोगों ने आधार और ई-केवाईसी इन सब चीजों का लाभ लिया है। उन्होंने कहा जनसुनवाई के दौरान यह सुविधायें लगातार जारी रहेंगी जैसे स्वास्थ्य शिविर दो-तीन जनसुनवाई से लगातार लग रहे हैं, अब यह पैटर्न बन गया है, यह भी लगातार जारी रहेगा, अब इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। प्रयास किया जायेगा कि इसमें और कुछ चीज ऐसी जोड़ सके जिसके लिए जनता को अलग-अलग जगह ना जाना पड़े, वे यहां आकर के बैठते हैं तो उन्हें यहीं पर लाभ मिल जाए। कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर बनाया जा सके। जनसुनवाई में आई पूजा नामदेव ने बताया यहां पर मुझे बहुत सी नई चीजें देखने को मिली है, पहले आते थे यहां कुछ भी नहीं था, यहां-वहां भटकते रहते थे कुछ नहीं होता था। अब आते हैं तो एक ही जगह पर सारी चीज है, आधार कार्ड भी सुधारे जा रहे हैं, सारी चीजें उपलब्ध है। राजेश अहिरवाल ने बताया आधार कार्ड अपडेट करवाने आए थे, यहां पर एक ही जगह पर सारी सुविधा मिल रही है। इससे अच्छा लग रहा है, अंदर सारी सुविधाएं हैं।

पुराना जिला पंचायत भवन परिसर में लगभग 200 विद्यार्थियों की लाइब्रेरी में पढ़ने की सुविधा की जा रही है-कलेक्टर

100 विद्यार्थियों की सुविधा

आज से शुरू हो जायेगी

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले के विद्यार्थियों से कहा दमोह में पुराना जिला पंचायत भवन है, वहाँ पर पहले से एक सरकारी लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है। उसी परिसर में हमने अभी एक और जगह निकाली है, जिसमें लगभग 80 से 100 विद्यार्थी एक साथ बैठ सकते हैं, इस प्रकार जिला पंचायत भवन के परिसर में लगभग 200 विद्यार्थियों की लाइब्रेरी में पढ़ने की सुविधा की जा रही हैं, 100 विद्यार्थियों की सुविधा आज यानी 11 सितम्बर से चालू हो जाएगी, आज उसका काफी काम हो गया है। कलेक्टर ने कहा उम्मीद है की 01 या 02 दिन में जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए या अन्य कार्यों से लाइब्रेरी में पढ़ने आते है, उनको एक न्यूनतम सुविधाओं के साथ अच्छी व्यवस्था मिलेंगी, जिससे वे यहाँ पर निःशुल्क अध्ययन निश्चिंत होकर कर सकेंगे। उन्होंने कहा 01 या 02 दिन में इसको पूरी तरह से प्रारम्भ कर दिया जायेगा, जो विद्यार्थी कहीं और बाहर पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो शहर के बीच में एक स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं का अध्ययन निःशुल्क करना चाहते हैं, वे अवश्य इस लाइब्रेरी को जॉइन कर सकेंगे।

तहसील पथरिया में हुई ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई

सीईओ पहुँची बांसाकला सुनी समस्याएं, हुआ मौके पर निराकरण

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, आज जिले की जनपद पंचायत पथरिया में तहसील स्तरीय जनसुनवाई की शुरुआत तहसीलदार एवं सीईओ जनपद पंचायत पथरिया दीपा चर्तुवेदी द्वारा प्रत्येक पंचायत में शुरू कराई गई। जिसके तहत वे स्वयं बांसा कला में मौजूद रहकर ग्राम वासियों की समस्याओं को सुना और प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण किया गया। इस संबंध में तहसीलदार एवं सीईओ जनपद पंचायत पथरिया दीपा चतुर्वेदी ने बताया कि आज जनपद पंचायत के अधीन आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस जनसुनवाई में पटवारी, पंचायत, सचिव और ग्राम स्तर के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया हरद्वानी में 10 आवेदन प्राप्त हुए थे सभी का निराकरण किया गया। यह भी बताया कि ग्राम मगरदा में रोड की ग्रामीणों द्वारा की जाने पर मौके पर इंजीनियर, सचिव, पटवारी और आर आई द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।

भगवान देवनारायण के जन्म पर निकला चल समारोह

युवाओं ने दिखाए हैरतंगेज करतब

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, भगवान देवनारायण के जन्म महोत्सव पर गुर्जर समाज द्वारा शहर में विशाल चल समारोह निकाला गया। मंगलवार सुबह गायत्री मंदिर से शुरू हुए चल समारोह में नगर सहित आसपास के गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। चल समारोह में समाज के युवाओं ने आकर्षक कलाबाजी का प्रदर्शन किया। शहर के महूपुरा, धानमंडी चौराहा, किला रोड, हुसैनी चौक, आजाद चौक, नई सडक़, बस स्टैंड होता हुआ चल समारोह एबी रोड स्थित गुर्जर छात्रावास पर पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हुआ। उल्लेखनीय है कि गुर्जर समाज द्वारा अपने आराध्य भगवान देवनारायण की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इसीके चलते इस वर्ष भी समाज के लोगों ने जयंती पर नगर में चल समारोह निकाला और जुलूस में समाज के नौजवानों ने अपनी कला का भी जमकर प्रदर्शन किया। जुलूस में सम्मिलित दर्जनों अखाड़े के सदस्य अपनी-अपनी कला कौशल में माहिर थे। यही कारण रहा कि किसी ने 15 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अपना जौहर दिखाया तो किसी ने लाठी की कला में दमखम दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया। वहीं गुर्जर समाज द्वारा शहर में निकाले गए चल समारोह का विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा जगह-जगह मंच लगाकर पुष्पवर्षा कर स्वागत-सत्कार किया।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रव्यापी देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 की प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल पर आरंभ

अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय पर्यटन स्थल को विश्व स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ भोपाल, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रव्यापी पहल, देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 की प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल पर आरंभ की है। इस अभियान के अंतर्गत निम्नानुसार श्रेणी यथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, विरासत, प्रकृति और वन्य जीवन एवं अन्य सहित सर्वश्रेष्ठ पर्यटक आकर्षणों पर सार्वजनिक धारणाएं एकत्र की जायेगीं। प्रत्येक श्रेणी में तीन स्थलों का चयन किया जायेगा। नागरिको को श्रेणी अनुसार अपनी पसंद के पर्यटन स्थल का चयन करने की सुविधा वोटिंग के आधार पर उपलब्ध कराई गई है। अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय पर्यटन स्थल को विश्व स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना है। इस अभियान को सार्वजनिक रूप से भागीदारी हेतु समस्त नागरिकों के लिये सुविधाजनक बनाने के लिए MyGo1 प्लेटफ़ॉर्म पर माइक्रो साइट विकसित किया गया है, जो नागरिकों को उपरोक्त श्रेणियों में अपने पसंदीदा पर्यटन स्थानों के लिए वोट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल 15 सितंबर 2024 तक ओपन है। इस अभियान में वोटिंग करने वाले नागरिकों को लक्की ड्रॉ के माध्यम से मध्यप्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल पर यात्रा करने का अवसर प्रदान किया जावेगा। साथ ही अभियान में वोटिंग हेतु प्रमाण-पत्र भी ऑनलाईन उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रेसवार्ता कर भाजपा नेता भड़ाना ने शाजापुर नगरपालिका पर लगाए धांधली के आरोप

निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री लगाकर लाखों रुपये का भ्रष्टाचार करने की दी जानकारी

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी कर धांधली करते हुए नगरपालिका के द्वारा लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम हेल्प लाईन पर शिकायत की गई है। सडक़ निर्माण से लेकर बाउंड्रीवाल तक में ठेकेदार से घटिया मटेरियल लगवाकर नगरपालिका गलत बिल पास कर रही है। यह आरोप भाजपा नेता संदीप भड़ाना ने मंगलवार को शहर के निजी होटल में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान शाजापुर नगरपालिका के जिम्मेदारों पर लगाए। पत्रकारवार्ता के दौरान भड़ाना ने बताया कि वार्ड क्रमांक 1 शाजापुर कल्याण देवतवाल जी के मकान से रजावत जी के मकान तक सीसी रोड़ जिसकी कुल लंबाई 96 मीटर चौड़ाई 5 मीटर लगभग मोटाई साढ़े तीन से साढ़े चार ईंच, एरिका हास्पिटल के पास माताजी मंदिर की वाल की लंबाई 33 मीटर है जिसकी गहराई 4 मीटर है। इसका बिल गलत बना हुआ है इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाईन पर भी है। इसी तरह वार्ड नं 2 तिवारी जी के मकान से जैन साहब के किराना तक सीसी रोड़ जिसकी कुल लंबाई 225 मीटर, चौड़ाई लगभग 3 से 4 मीटर, मौटाई साढ़े तीन से चार इंच है। वहीं वार्ड नंबर 7 इमामवाड़ा मैदान का बिल गलत बना है जिसकी नपती करने से नपा के जिम्मेदारों ने मना कर दिया है। इसी तरह अन्य वार्डों में बनाई गए सीसी रोड में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दुपाड़ा रोड़ पर चल रहे एचडीआरए नाली निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग की जा रही है। इसी तरह मुख्यमंत्री अधोसंरचना का जो कार्य किया गया है वह भी गुणवत्ताहीन है जिसकी लंबाई 468 मीटर है, चौड़ाई लगभग 7 मीटर, मोटाई पांच से छ: इंच है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना में ही दूसरा रोड बीकेएसएन कालेज की सामने वाली नहर से शुरू होकर नागर किराना स्टोर रोड़ से पहले तक जिसकी चौड़ाई लगभग 6.30 है और मोटाई 6 इंच है, जबकि नियमानुसार 8 इंच होनी चाहिए। इसी योजना में तीसरा रोड़ आदर्श कालोनी में अशोक आटो गैरिज से शुरू होकर गोहिल हास्पिटल होते हुए खाटूश्यामजी मंदिर तक है जिस रोड़ में सीमेंट की मात्रा बहुत कम की गई है। भड़ाना का कहना है कि एक फिलोरी मशीन में 16 से 18 बेग सीमेंट के लगते हैं लेकिन निर्माण कार्य में महज 9 से 11 बेग ही लगाए जा रहे हैं। साथ ही वार्ड 29 फूलखेड़ी हनुमान मंदिर के पीछे नहर के पास नहर से स्वस्तिक गार्डन से शुरू होकर राधेश्याम मालवीय जी के मकान तक सीसी रोड़ लंबाई लगभग 145 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, मोटाई लगभग चार इंच है। इन्हीं सभी कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसकी शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। भड़ाना ने बताया कि वह नगरपालिका में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत कार्रवाई नही होने तक करते रहेंगे।

मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने दान पत्र से नकदी की साफ

इनवर्टर सहित अन्य सामान भी किया चोरी

गौरव सिंघल। सिटी चीफ सहारनपुर (रामपुर मनिहारान)। गांव सलेमपुर के पास गंगोह मार्ग पर स्थित मंदिर का बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर में रखे दान पत्र से नकदी, इनवर्टर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरी की उक्त घटना की तहरीर ग्रामीणों द्वारा कोतवाली रामपुर में दे दी गई है। ग्रामीण जयकुमार भगत जी, मांगेराम, मुकेश कुमार, सोनू प्रधान, शेर सिंह, अजय पंवार, ग्राम प्रधान पिंकी देवी, सुरेंद्र कुमार, रामपाल आदि ने कोतवाली रामपुर में मंदिर में चोरी की इस घटना की तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।

विक्रेता दिनेश सिंह राठौर ने की अनैतिक लाभ अर्जित करने की हेराफरी

जैतहरी में शासकीय दुकान महुदा एवं चोरभठी में 11 लाख के शासकीय खाद्यान्न की हुई कालाबाजारी

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनूपपुर, जिले में शासकीय खाद्यान्न के हेराफेरी एवं कालाबाजारी के लगातार मामले सामने आ रहे है, जहां सहकारी समिति धनगवां के शासकीय उचित मूल्य की दुकान महुदा एवं शासकीय दुकान चोरभटी के विक्रेता दिनेश सिंह राठौर द्वारा हितग्राहियों से पीओएस मशीन में अंगूठा लगाकर राशन नही दिए जाने के मामले की शिकायत पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीमा सिन्हा ने शासकीय दुकान महुदा एवं शासकीय दुकान चोरभठी का भौतिक सत्यापन किया गया, जहां जांच में विक्रेता दिनेश सिंह राठौर द्वारा उक्त खाद्यान्न के स्टॉक का अवैध रूप से विक्रय कर अनैतिक लाभ अर्जित करते हुए शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी करना पाया गया है। जानकारी के अनुसार विक्रेता दिनेश सिंह राठौर जो कि सहकारी समिति धनगवां के प्रबंधक सालिक राठौर का साला है। जिसने वर्ष 2019 में बिना भर्ती निकले ही फर्जी प्रस्ताव से सालिक राठौर ने दिनेश कुमार राठौर की भर्ती विक्रेता के रूप में की गई थी।

यह है मामला- जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान महुदा में शासकीय खाद्यान्न के हेराफेरी किए जाने की शिकायत पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीमा सिन्हा द्वारा 29 अगस्त की सुबह लगभग 12 बजे उक्त दुकान पहुंची, जहां दुकान बंद पाई गई, जिसके बाद विक्रेता दिनेश सिंह राठौर को फोन कर बुलाया गया, लेकिन विक्रेता ने 15 मिनट में आने की बात कहते हुए अपना मोबाइल बंद कर लिया था, जिसकी सूचना कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीमा सिन्हा ने समिति प्रबंधक धनगवां सालिक राठौर को दी, जिसके बाद प्रबंधक सालिक राठौर मौके पहुंचे। लेकिन विक्रेता के नही पहुंचने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने ग्रामीणों की उपस्थिति में उक्त दुकान को सील कर दिया था। जहां प्रबंधक सालिक राठौर ने विक्रेता दिनेश कुमार राठौर को लाने के लिए एक दिवस का समय की मांग की गई थी।

महुदा दुकान के स्टॉक में मिली बड़ी गड़बड़ी- पूरे मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा दूसरे दिन महुदा दुकान का सील खोलते हुए धनगवां समिति के प्रबंधक, विक्रेताओं दिनेश सिंह राठौर एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, जहां सत्यापन में शासकीय खाद्यान्न की हेराफेरी एवं कालाबाजारी सामने आई। जांच में 22.88 क्विंटल गेहूँ, 141.29 क्विंटल चावल, 41 किलो शक्कर एवं 9.19 क्विंटल नमक अनुमानित कीमत 6 लाख 29 हजार 3775 रूपए कम पाया गया।

चोरभठी दुकान में जमकर की गई कालाबाजारी- शासकीय उचित मूल्य की दुकान महुदा के विक्रेता दिनेश सिंह राठौर द्वारा शासकीय खाद्यान्न की जमकर कालाबाजारी की गई। जिस पर उक्त विक्रेता दिनेश सिंह राठौर को अतिरिक्त दी गई शासकीय दुकान चोरभठी की जांच भी की गई, जहां जांच के दौरान पाया गया कि विक्रेता दिनेश सिंह राठौर द्वारा पीओएस मशीन में हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर उनके खाद्यान्न ही नही दिया गया, जिसके बाद चोरभठी दुकान का भी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा स्टॉक का सत्यापन किया गया, जहां चोरभठी दुकान में लगभग 42 क्विंटल गेहूँ, 86 क्विंटल चावल एवं 1 क्विंलटल 30 किलो नमक अनुमानित कीमत 4 लाख 56 हजार 778 रूपए कम पाया गया। जहां कनिष्ठा आपूर्ति अधिकारी शासकीय उचित मूल्य की दुकान महुदा एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान चोरभठी में 11 लाख रूपए के शासकीय खाद्यान्न की हेराफेरी करते हुए कालाबाजारी करने पर कार्यवाही की गई है।

एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा प्रकरण- महुदा एवं चोरभठी शासकीय दुकान में लगभग 11 लाख के शासकीय खाद्यान्न की हेराफेरी के मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीमा सिन्हा ने विक्रेता दिनेश सिंह राठौर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिकाओं के उल्लंघन पर प्रकरण तैयार करते हुए वसूली एवं अभियोजन की कार्यवाही हेतु प्रकरण एसडीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा।

इनका कहना है- शासकीय दुकान महुदा एवं चोरभठी का प्रकरण तैयार कर एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

डीएम मनीष बंसल ने की मेला गुघाल की तैयारियों की समीक्षा

साफ-सफाई के साथ ही सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतेजाम

कैमरों की निगरानी में होगा मेला, बनेगा कन्ट्रोल रूम

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में 13 सितम्बर से 05 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले मेला गुघाल की तैयारियों तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में डीएम मनीष बंसल ने मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे, बिजली, पेयजल, मजबूत बैरिकेटिंग, साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्कृति एवं राष्ट्रीयता को बढाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि सभी विभाग सौंपी गयी जिम्मेदारियों का भली प्रकार से निर्वहन करना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु एंबुलेंस एवं चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। मौसम के अनुसार नाले एवं नालियों की साफ-सफाई के साथ ही फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएं। उन्होंने कहा कि पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाएं। सुविधाओं एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाए। मेले में सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। खाद्य पदार्थों की जांच की जाए एवं प्रसाद के विक्रेताओं को सवास्थ्य के दृष्टिगत प्रसाद को ढककर रखने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था बेहतर रखी जाए। बिजली के तार लटके न हों। पीडब्ल्यूडी द्वारा झूलों का तकनीकी परीक्षण करना सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी स्ट्रक्चर बिना अनुमति के न लगाया जाए। अग्निशमन विभाग को सुरक्षा के तहत प्रयाप्त मात्रा में आकस्मिक स्थिति में अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, नगर मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 प्रवीण कुमार, अपर नगर आयुक्त राजेश यादव सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को अदालत ने सुनाई सात वर्ष के कारावास की सजा

दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

गौरव सिंघल। सिटी चीफ सहारनपुर, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार शाश्वत पांडेय ने गैर इरादतन हत्या में दोषी नूर बस्ती नगर कोतवाली निवासी दानिश और अरशद को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा दोषियों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सन् 2022 में सूंघने के लिए सुलोचन न देने पर अकरम को दानिश और अरशद ने मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट अकरम की मां गीता ने कोतवाली सदर बाजार में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

विधायक मुकेश चौधरी एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जल जीवन मिशन के तहत की हर घर नल-हर घर जल योजना की समीक्षा

जिलाधिकारी ने कम्पनियों को कार्यशैली में सुधार लाने की दी चेतावनी

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल-हर घर जल योजना की समीक्षा हेतु जनपद में किये गये कार्यों की प्रगति के संबंध बैठक आहूत की गयी।विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी ने हर घर जल योजना के तहत बेहतर कार्ययोजना बनाकर रेस्टोरेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना इस तरह से बनाई जाए जिससे जन सामान्य को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आने पाए। शिथिल प्रगति पर कंपनियां बहाना ना बनाएं, बल्कि कार्य योजना बनाएं की निर्धारित अवधि में लक्षित कार्य कैसे पूर्ण करना है। उन्होने कहा कि हर घर नल-हर घर जल केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनहित में महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकता की योजना है, इस योजना के धरातल पर क्रियान्वयन में लापरवाही न हो। उन्होंने बैठक में अपनी विधानसभा के 93 ग्रामों में किए जा रहे कार्यों का फीडबैक देते हुए अपने सुझाव दिए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने समीक्षा के दौरान कहा कि गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। जहां पर रेस्टोरेशन का कार्य खराब है वहां दोबारा किया जाए। इसके लिए उन्होने टीपीआई को मौके पर जाकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पर पाईपलाईन कार्य पूर्ण हो चुका है वहां पर टीम लगाकर रेस्टोरेशन का कार्य 30 सितम्बर तक पूर्ण किया जाए। उन्होंने जनपद में कार्य कर रही कम्पनियों को निर्देश दिए कि टीमों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रतिदिन जिओटैग फोटो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि अतिरिक्त टीम लगाकर कार्य में तेजी लाएं। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गये फीडबैक के आधार पर कार्य को प्राथमिकता से किया जाए। किए जा रहे कार्यों का अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। कमी पाए जाने एवं गलत जानकारी उपलब्ध कराने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता को सख्त निर्देश दिए कि अपने पर्यवेक्षण कार्य में सुधार लाना सुनिश्चित करे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, पीडी डीआरडीए प्रणय कृष्ण, अधिशासी अभियन्ता जल निगम अनुज कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण तथा कार्यदायी संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कोतमा सूदखोरपर हुई कार्यवाही

50 हजार के कर्ज में 60 हजार की वसूली, सूदखोर हुआ गिरफ्तार

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ । अनूपपुर। मध्य प्रदेश की अनूपपुर पुलिस ने एक सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई की है. आरोपी मोहम्मद अफजल 50 हजार रुपए 10 प्रतिशत ब्याज पर एक शख्स को दिया था. जब उसने ब्याज सहित पैसा वापस किया तो आरोपी ने उसका एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया. फरियादी के शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे धर दबोचा.यह कार्रवाई कोतमा थाना पुलिस ने की है. थाना प्रभारी सुंदरेश मरावी ने बताया कि फरियादी मोहम्मद नियाज सूदखोरी की शिकायत दर्ज कराया था. उसने बताया था कि 15 जुलाई को मोहम्मद अफजल निवासी लहसुई से 50 हजार रुपए काम के लिए 10 प्रतिशत प्रति माह के दर से कर्ज लिया था. जिसके लिए आरोपी ने ,ञ्जरू कार्ड अपने पास रख लिया था.मूलधन सहित कुल 60 हजार रुपए आरोपी को दिया था. अपना ,ञ्जरू कार्ड अफजल से वापस मांगने पर वापस नहीं कर रहा था. वह कहता था कि अभी मेरे दिए हुए कर्ज के रुपए का ब्याज बाकी है. अगर ब्याज का पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो,ञ्जरू कार्ड नहीं दूंगा. इतना ही नहीं अफजल ने उसे जान से मारकर की भी धमकी दी थी. पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस इस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

वृक्ष पुण्य के द्वार है, धरती मां के श्रंगार है

पर्यावरण मित्रो ने मुक बधिर / दृष्टि बाधित /मंद बुद्धि आवासीय छात्रावास में पौधा रोपण कर चलाया स्वच्छता अभियान

नीमच/ स्वच्छ नीमच हरित नीमच के लिए संकल्पित सामाजिक संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था नीमच निरन्तर अभियान चला कर शहर को स्वच्छ सुंदर पर्यावरण युक्त प्रदूषण मुक्त बनाने में जुटी हुई है संस्था द्वारा शहर से गांव तक चहुंओर पोंधे रोपित कर धरती मां के आंचल पर हरियाली की चादर बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, संस्था के सेवा भावी सदस्य नियमित 2 से 3 घंटे श्रमदान कर शहर को स्वच्छ सुंदर पर्यावरण युक्त बनाने में जुटे हुए हैं, संस्था सदस्यों द्वारा मंगलवार दिनांक 10 सितंबर 2024 को शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 खेल मैदान स्थित सी डब्ल्यू एस एन (मुक बधिर, दृष्टि बाधित,मंद बुद्धि आवासीय) छात्रावास में प्रात: 7 से 9 बजे तक 2 घंटे श्रमदान कर छात्रावास परिसर से गाजर घास कंटीली झाड़ियों की साफ-सफाई कर गंदा कचरा, प्लास्टिक पोलेथिन थैलियां एकत्रित कर परिसर में फलदार छायादार फुलदार ओषधि युक्त नीम, कचनार,कदम, गुलमोहर, चम्पा,आम आदि के पोंधे रोपित कर पेड़ बनाने का संकल्प लिया, संस्था अध्यक्ष किशोर बागड़ी सचिव डॉ राकेश वर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा पुर्व में भी छात्रावास परिसर में कई पोंधे रोपित किए गए थे जो 20 से 25 फिट के पेड़ का आकार ले चुके थे को कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने स्वार्थ की खातिर 5 - 7 हरे भरे लहलहाते पेड़ों को निर्दयतापूर्वक काट दिए गए थे जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी जिस पर कोई कार्रवाई न होने से आए दिन शहर में कहीं न कहीं हरे भरे लहलहाते पेड़ों को निर्दयतापूर्वक काट कर शहर के पर्यावरणीय वातावरण को नष्ट किया जा रहा है, जिला प्रशासन, फारेस्ट विभाग, नगरपालिका नीमच को चाहिए कि ऐसे लोगों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएं ताकि भविष्य मे कोई हरे भरे लहलहाते पेड़ों को न काटें, संस्था संरक्षक नवीन अग्रवाल ने बताया कि एक छोटे-से पोंधे को रोपित कर उसे छोटे से बच्चे की तरह देखभाल कर बड़ी मुश्किल से उसे पेड़ बनाने तक कड़ी मेहनत करना पड़ती है तब जा कर ये पेड़ बनते हैं, वृक्ष भी एक प्राणी की तरह है जो प्रकृति को संवारने के साथ ही हमें जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु आक्सीजन प्रदान करते हैं, ऐसे पुण्यदाई वृक्षों को स्वार्थ की खातिर निर्दयतापूर्वक काटा जाना प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, अभियान में संस्थापक संरक्षक इंजिंनियर नवीन कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष किशोर बागड़ी, सचिव डॉ राकेश वर्मा, रमेश मोरे, राजकुमार सिन्हा, केशव सिंह चौहान,सीताराम शर्मा, प्रकाश बानोदा,भुरा भाई सिंधी,सीडब्ल्यू एस एन छात्रवास के सेवाभावी मदनलाल यदुवंशी, प्रकाश दायमा, सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता रुपेश जाधव भोपाल सिंह ठाकुर, गोपीलाल मालवीय आदि ने परिसर में स्वच्छता अभियान चला कर पौंधा रोपण कार्य में 2 घंटे श्रमदान कर सहभागिता निभाई, उक्त जानकारी संस्था सह सचिव केशव सिंह चौहान ने दी है, डॉ राकेश वर्मा प्रवक्ता संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था नीमच

RGPV घोटाले मामलें के फरार आरोपी राकेश सिंह राजपूत (तत्कालीन कुलसचिव राजीव गांधी प्रौघोगिकी विश्वविघालय) से नगदी 30 लाख एवं 02 एप्पल कंपनी के मोबाईल बरामद

मामले का संक्षिप्त विवरण दिनांक 03.03.24 को राजीव गांधी प्रौघोगिकी विश्वविघालय के कुल सचिव डॉ0 मोहन सेन ने आरोपी 1. सुनील कुमार तत्कालीन कुलपति 2. आर.एस. राजपूत, तत्कालीन कुलसचिव 3. ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन वित्त नियत्रंक 4. कुमार मयंक 5. दलित संघ सोहागपुर एवं अन्य के विरूद्ध विश्वविघालय में विगत वर्षो में अनियमितता एवं अनाधिकृत रूप से आपराधिक षडयंत्र कर विश्वविघालय की राशि 19.48 करोड रूपये निजी खातों में अंतरित किये जाने की रिपोर्ट किये थे जिस पर थाना गांधीनगर भोपाल में अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं (संशोधन अधिनियम 2018) किया जाकर प्रकरण की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त बैरागढ नगरीय भोपाल द्वारा एस.आई.टी. के साथ मिलकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान पाये गये साक्ष्य एवं की गई कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य से आरोपी 1. सुनील कुमार गुप्ता तत्कालीन कुलपति आरजीपीव्ही, 2. कुमार मयंक तत्कालीन टास्क हेड आरबीएल बैंक, 3. रामकुमार रघुवंशी तत्कालीन शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक पिपरियॉ, 4. सुनील रघुवंशी संयुक्त सचिव दलित संघ सोहागपुर, 5. ऋषिकेश वर्मा तत्कालीन वित्त नियत्रंक आरजीपीवी, 6. श्रीमती सीमा वर्मा, 7. रोहित रघुवंशी, 8. नंदकिशोर रघुवंशी, 9. शिवम मैखुरी, 10. श्रीमती रश्मि मिश्रा को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय चालान प्रस्तुत किया गया और उसके उपरांत प्रकरण की विवेचना धारा 173(8) जा0फौ0 में जारी रखते हुए आरोपी रतन उमरे, सचिव दलित संघ सोहागपुर को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। प्रकरण में आरोपी राकेश सिंह राजपूत पिता स्व0 बंशीधर राजपूत उम्र-58 साल निवासी बी0पी0-01, लेकपर्ल गार्डन एयरपोर्ट रोड भोपाल तत्कालीन कुलसचिव राजीव गांधी प्रौघोगिकी विश्वविघालय भोपाल की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दिनांक 22.08.24 को जमानत याचिका निरस्त कर दी गई और माननीय न्यायालय निर्देश के पालन में आरोपी राकेश सिंह राजपूत दिनांक 05.09.24 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और संबंधित प्रकरण में पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड में लेकर आरोपी से पूछताछ की गई। प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि आरोपी कुमार मयंक, मैनेजर आरबीएल बैंक एवं रामकुमार रघुवंशी, ब्रांच मैनेजर एक्सिस बैंक पिपरिया द्वारा राजीव गांधी प्रौघोगिकी विश्वविघालय से राशि प्राप्त करने के उपरांत इनके द्वारा प्रदाय की गई राशि में से आरोपी राकेश सिंह राजपूत अपने तथा परिजन के खातों में 17,64,000/-रूपये राशि नगद जमा की गई है। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी राकेश सिंह राजपूत से आरोपीगणों द्वारा प्रदाय की गई राशि में से 30 लाख रूपये नगद एवं आरोपी कुमार मयंक के द्वारा दिए गए 02 एप्पल कंपनी के मोबाईल फोन कीमती करीबन 1,50,000/- रूपये के जप्त किये गये है। आरोपी राकेश सिंह राजपूत द्वारा आरोपी कुमार मयंक एवं रामकुमार रघुवंशी से गबन की राशि नगदी रूप में प्राप्त कर जिला ग्वालियर में स्थित प्लाट क्षेत्रफल 23ग्49 स्क्वायर फिट में करीबन 70 लाख रूपये का 04 फ्लोर भवन निर्माण कार्य कराया गया है जो तैयार होकर किराये पर दिया गया है एवं लश्कर ग्वालियर में प्लाट क्षेत्रफल 48ग्85 स्क्वायर फिट में करीबन 90 लाख रूपये का भवन निर्माण 05 फ्लोर में कार्य कराया गया है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। प्रकरण में पुलिस रिमाण्ड के उपरांत आरोपी राकेश सिंह राजपूत को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश सिंह राजपूत को केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया।

खेलो से होता है शारीरिक और मानसिक विकास

एकल, संस्कृति महोत्सव और गणित विज्ञान प्रतियोगिता हुई संपन्न

उज्जैन

उज्जैन जिला ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला उज्जैन द्वारा संचालित सेदरी संकुल के विद्यालयो की संकुल स्तरीय एकल, संस्कृति महोत्सव, गणित विज्ञान प्रतियोगिता सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मड़ावदा में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में संकुल क 11 विद्यालयों से 325 भैया बहिनों की सहभागिता रही। उद्घाटन समारोह में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में अतिथि हुकूमसिंह गौड़ (जिला प्रमुख उज्जैन), कन्हैयालाल गामी(वरिष्ठ समाजसेवी) , अशोक पाटीदार(संकुल प्रमुख सेदरी संकुल),दरबारसिंह राठौर (प्रतियोगिता संयोजक, सह संकुल प्रमुख) ,दशरथ चौहान (अध्यक्ष - मड़ावदा देवरस शिक्षा विकास समिति) , प्रकाश राठोड़ (उपाध्यक्ष - मड़ावदा देवरस शिक्षा विकास समिति मंचासिन रहे। शिशु और बाल वर्ग में एकल प्रतियोगिता में 100,200,400,600 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कुद, गोला फेंक, चक्का फेंक संपन्न हुई। बौद्धिक प्रतियोगिता शिशु और बाल वर्ग में व्यक्तिगत गीत, निबंध, रंगोली, चित्रकला, एकल भजन,कथाकथन, एकल अभिनय, स्वरचित कविता पाठ, वंदे मातरम, मानस प्रथमाक्षरी, शास्त्रीय गायन, नृत्य, तबला वादन,मूर्तिकला , संस्कृति ज्ञान, वैदिक गणित और विज्ञान प्रश्नमंच, गणित और विज्ञान पत्रवाचन, गणित और विज्ञान प्रयोग, गणित विज्ञान प्रदर्श आदि प्रतियोगिताएं सम्पन्न हुई। समापन और पुरूस्कार वितरण समारोह में अतिथि श्री रामेश्वर सेकवाड़िया(अध्यक्ष - ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला उज्जैन), श्री हुकुमसिंह गौड (जिला प्रमुख - उज्जैन), बाबूलाल नागर (संकुल संयोजक), कचरुलाल प्रजापत (सचिव - मड़ावदा देवरस शिक्षा विकास समिति), दरबार सिंह राठौर (प्रतियोगिता संयोजक) मंचासीन रहे। जिला प्रमुख ने अपने उद्बोधन में प्रतियोगिता की भूमिका,भैया बहिनों को खेल के प्रति स्नेह, प्रतियोगिताये विभिन्न कलाओ के विकास का केंद्र होती है। भैया बहिनो को हमेशा खेल गतिविधि में भाग लेना चाहिए जिससे शारिरिक और मानसिक विकास होता है। आपने बताया कि विद्या भारती अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता संपन्न कराती है। विद्या भारती को एसजीएफआई में एक प्रांत (राज्य) की मान्यता प्रदान की गई है। इस संकुल के भैया बहिन वहा तक पहुंचे।और आपने विजेता भैया बहिनों को बधाई देते हुए जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयार रहने की बात कही। सभी विजेता भैया बहिनों को अतिथियों द्वारा पुरुस्कृत किया गया। कुल 78 प्रकार की प्रतियोगिताओं में 90 भैया बहिनों ने प्रथम और 80 ही भैया बहिनों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता को संपन्न कराने वाली संचालन टोली में सरंक्षक रामेश्वर सेकवाड़िया, पालक हुकुमसिंह गौड़, संयोजक दरबार सिंह राठौर, महाप्रबंधक घनश्याम पाटीदार, मुख्य शिक्षक और एकल प्रतियोगिता प्रभारी देवीलाल खमोरिया, संस्कृति महोत्सव प्रभारी श्रीमती रजनी शर्मा,संस्कृति महोत्सव सहप्रभारी लोकेश कुमावत, गणित विज्ञान मेला प्रभारी अशोक पाटीदार, दौड़ में देवीलाल खमोरिया,महिपालसिंह डोडिया, रोहित मंडावलिया, ऊंची और लंबी कुद में रणजीत सिंह डोडिया, अर्जुन सालित्रा, गोला चक्का फेंक में ईश्वरलाल धाकड़, लखन खमोरिया, पवन अटोलिया , वैदिक गणित और विज्ञान प्रश्नमंच में घनश्याम पाटीदार, दिलीप वाक्तरिया, पवन वाक्तरिया, संस्कृति ज्ञान प्रश्नमंच में लोकेश कुमावत,दशरथ गरगामा, जितेंद्र ढोढ़रिया, चित्रकला, रंगोली, निबंध में श्रीमती रजनी शर्मा, श्रीमती टीना सेन, श्रीमती राजू गरगामा, व्यक्तिगत गीत, एकल भजन, गीता पाठ, एकल अभिनय में श्रीमती यमुना खमोरिया, नीता पाटीदार, सुश्री सविता बैरागी , वंदे मातरम, मूर्तिकला में लोकेश कुमावत, श्रीमती निर्मला प्रजापत, तबला वादन, शास्त्रीय नृत्य, गायन में श्रीमती रजनी शर्मा, पूजा खमोरिया, मानस प्रथमाक्षरी, कथाकथन, स्वरचित कविता पाठ मे दरबार सिंह राठौर, विजय सक्सेना,गणित विज्ञान पत्रवाचन, प्रदर्श, प्रयोग निर्णायक के रूप में भाटपचलाना के आचार्य श्रवनसिंह सोलंकी, रोहित मंडावलिया, अशोक पाटीदार ,कार्यालय में दशरथ गरगामा, श्रीमती पायल राठौड़, प्रचार प्रसार में निखिल मदारिया, श्रीमती ज्योति नायक, भोजन संदीप प्रजापत और स्थानीय विद्यालय के आचार्य दीदी, संरक्षक आचार्य दीदी,समिति का सहयोग से प्रतियगिता संपन्न हुईं। उदघाटन समारोह में संचालन देवीलाल खमोरिया, अतिथि परिचय लोकेश कुमावत , स्वागत घनश्याम पाटीदार, दशरथ गरगामा, ईश्वरलाल धाकड़ और समापन में संचालन लोकेश कुमावत, अतिथि परिचय घनश्याम पाटीदार, स्वागत श्रीमती रजनी शर्मा, श्रीमती यमुना खमोरिया, श्रीमती नीता पाटीदार ने किया।प्रतियोगिता की घोषणा एकल में देवीलाल खमोरिया, बौद्धिक में लोकेश कुमावत द्वारा की गई।भोजन व्यय स्थानीय विद्यालय समिति द्वारा किया गया। सेदरी संकुल की प्रतियोगिता में सकतखेड़ी, चापानेर,मोकडी, आक्याजागीर, चापाखेड़ा, सेदरी, बरखेड़ा जावरा, बंजारी, बटलावदी, मड़ावदा और कमठाना विद्यालय के भैया बहिनों ने सहभागिता की।अब संकुल के विजेता भैया बहिन जिला स्तरीय प्रतियोगिता महिदपुर तहसील के जगोटी विद्यालय में 12 सितंबर को सेदरी संकुल का प्रतिनिधत्व करेगें ।

कलेक्टर श्री सिंह ने जनसुनवाई में आये दिव्यांग आवेदक मोहम्मद अनीस को तत्काल दिलवाई मोटोराईज्ड

भोपाल

जनसुनवाई में 92 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए

कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को जनसुनवाई बैठक हुई। बैठक में आये दिव्यांग आवेदक श्री मोहम्मद अनीस पिता को सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से एक बैटरी वाली मोटोराईज्ड ट्राईसाइकल वितरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई एडीएम श्री भूपेंद्र गोयल, श्री अंकुर मेश्राम, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती निधि चौकसे एवं डिप्टी कलेक्टर श्री अजय शर्मा उपस्थित रहे।कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर हितग्राही को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अंकुर मेश्राम द्वारा एक मोटोराईज्ड ट्राईसाइकल दी गई। आवेदक के दस्तावेजों का पात्रता परीक्षण संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय भोपाल श्री आर.के.सिंह द्वारा किया गया है जिसमें हितग्राही पात्रतानुसार 80 प्रतिशत दिव्यांग एवं भोपाल जिले का निवासी पाया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने बैटरी वाली मोटोराईज्ड ट्राईसाइकल के क्रय करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल को निर्देश दिए गए थे। प्राप्त निर्देशानुसार मोटोराईज्ड ट्राईसाइकलों का क्रय मेसर्स एचएचडब्ल्यू केयर प्रोडक्ट इंदौर के माध्यम से किया गया था जिसका भुगतान खनिज विभाग भोपाल के पीएमएफ फंड से कराया गया था।

रतलाम ग्राम पंचायत कल्मोडा से खिमापड़ा रोड़ 50 वर्ष से निवास कर रहे, समस्त नागरिक लेकिन आज तक डामरीकरण रोड़ की मंजूरी नहीं हुई है। जिसके कारण आम नागरिक को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्त नागरिक खिमापड़ा कार्यालय पंचायत कल्मोडा

दोहरे शतकवीर राठौड़ का हुआ

उज्जैन

भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय खाचरोद, नागदा के द्वि शतक वीर अभिकर्ता, सुनिल राठोड़ ने वर्ष 2025 का प्रथम एम .डी.आर. टी.(मिलियन डॉलर राउंड टेबल) बनने का गौरव पुर्ण इतिहास रचा है । सुनिल राठोड़ ने वर्ष 2025 के लिए ,यू. एस. ए. में होने वाले विश्व स्तरीय (एम.डी.आर.टी.)सम्मेलन में सहभागिता हेतु पात्रता हासिल की है । सुनिल राठोड़ विगत कई वर्षों से इस तरह की उपलब्धि हासिल कर पूरे मध्य क्षेत्र में नाम दर्ज किया है । इस अवसर पर शाखा खाचरोद के शाखा प्रबंधक व वरिष्ठ अभिकर्ताओं एवम् विकास अधिकारियों द्वारा सपरिवार सम्मानित किया गया । इस उत्कृष्ट कार्य पर सुनिल राठोड़ में अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया । और सभी बीमा धारको का हृदय से आभार प्रकट किया । इस अवसर पर शाखा प्रबंधक नागदा ललित बुंदेला, शाखा प्रबंधक खाचरोद तेजप्रकाश वर्मा सहायक शाखा प्रबंधक जय किशन मीणा, विकास अधिकारी अशोक बबेरवाल, प्रहलाद सोलंकी, प्रेम, भरत सिसौदिया आदि ने सहयोग व मार्ग दर्शन पुर्ण किया है ।

बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिये सागरताल के सामने तैयार हो रहा है विशाल अस्थायी जलाशय

ग्वालियर

कलेक्टर एवं एसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ लिया जायजा

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के दिए निर्देश

सुरक्षा को ध्यान में रखकर होगी पुख्ता बेरीकेटिंग और संयुक्त दल रहेगा तैनात

भगवान श्रीगणेश की बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा ग्वालियर शहर में सागरताल के सामने वैकल्पिक जलाशय तैयार कराया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सगर ने अन्य अधिकारियों के साथ मंगलवार की शाम अस्थायी जलाशय स्थल का जायजा लिया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती चौहान ने नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाओं को इस प्रकार से अंतिम रूप दें कि श्रद्धालुजन सुविधाजनक तरीके से और धार्मिक विधि विधान के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकें। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एहतियात बतौर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएँ। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि सागरताल के सामने की मुख्य सड़क से वैकल्पिक जलाशय तक पर्याप्त चौड़ाई में गिट्टीयुक्त पहुंचमार्ग तैयार कराएँ। पहुँचमार्ग से लेकर विसर्जन स्थल तक पुख्ता बेरीकेटिंग भी कराई जाए। विसर्जन स्थल पर प्रतिमाओं की पूजा करने के लिये मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। साथ ही कहा अस्थायी जलाशय सहित सम्पूर्ण पहुँच मार्ग पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करें। लाईट, माइक व टेंट की भी पुख्ता व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक जलाशय के पास पर्याप्त संख्या में अस्थायी शौचालय व पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। विसर्जन सम्पन्न होने तक निर्वाध बिजली आपूर्ति के लिये वैकल्पिक रूप से बड़े जनरेटर की व्यवस्था करने पर भी कलेक्टर ने विशेष बल दिया। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने शहर भर से आने वाली बड़ी और छोटी प्रतिमाओं के सात मुख्य सड़क मार्गों सहित इन्हें जोड़ने वाली अन्य सड़कों की मरम्मत अभियान बतौर भरवाए जाएँ। साथ ही सभी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट चालू हालत में रहें। इन सभी सड़क मार्गों के ऊपर होकर गुजर रहे तार व्यवस्थित कराएँ, जिससे वाहनों से मूर्तियाँ सुगमता के साथ सागरताल के समीप स्थित अस्थायी जलाशय तक पहुँच सकें।

लगभग पाँच हजार वर्गफीट में तैयार हो रहा है अस्थायी जलाशय सागरताल के सामने भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लगभग पाँच हजार वर्गफीट और 12 फीट गहराई में अस्थायी जलाशय का बनाया जा रहा है। नगर निगम की जमीन पर बड़ी-बड़ी मशीनों के माध्यम से युद्ध स्तर पर इस तालाब को तैयार करने का काम जारी है।

सागरताल के सामने बनाए गए अस्थायी जलाशय में बड़ी प्रतिमाओं एवं छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग-अलग व्यवस्था रहेगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार व श्री टी एन सिंह, नगर निगम के अपर आयुक्त श्री मुनीष सिकरवार, एसडीएम श्री अतुल सिंह, श्री अशोक चौहान व श्री नरेन्द्र बाबू यादव तथा लोक निर्माण, विद्युत वितरण कंपनी तथा नगर निगम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

विसर्जन में सहयोग व सुरक्षा के लिए संयुक्त दल बनाएँ कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सगर ने अस्थायी जलाशय पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व मूर्तियों को धार्मिक भावनाओं के अनुरूप विसर्जित कराने के लिये संयुक्त दल गठित करने के निर्देश भी दिए। इन दल में नगर निगम, एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रबंधन) व पुलिस सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को शामिल करें। पारंपरिक रूप से प्रतिमाओं का विसर्जन कराने वाले केवट समुदाय के वॉलेन्टियर को भी इस दल में शामिल किया जाए। उन्होंने इन वॉलेन्टियर को सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए। साथ ही वॉलेन्टियर से कहा कि प्रतिमाओं का विसर्जन कराने के लिए किसी से भी अनावश्यक धनराशि की मांग न की जाए।

ग्वालियर शहर में श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए स्थल निर्धारित जिला प्रशासन और नगर निगम ने भक्त जनों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विसर्जन स्थलों का निर्धारण किया गया है।

बड़े आकार की प्रतिमाओं के लिए व्यवस्था भगवान श्री गणेश जी की बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बहोड़ापुर स्थित सागरताल के सामने स्थित खाली स्थान पर अस्थाई जलाशय बनाया गया है। यह जलाशय प्रतिमा विसर्जन के दौरान भक्तों को सुविधाजनक रहेगा और विसर्जन प्रक्रिया को सुगम बनाएगा।

छोटे आकार की प्रतिमाओं के लिए व्यवस्था छोटी आकार की श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कटोरा ताल के कोने पर एक छोटा कुंड तैयार किया गया है। यह व्यवस्था छोटे आकार की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, ताकि विसर्जन प्रक्रिया सरल और प्रभावी हो सके।

चलित जलाशय की व्यवस्था नगर निगम ने जन सहयोग से मुख्य मार्गों पर वाहनों के माध्यम से चलित जलाशय भी चलाए जाने की व्यवस्था की है। इन चलित जलाशयों के माध्यम से भक्तजन भगवान गणेश जी की छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। यह व्यवस्था उन भक्तों के लिए है जो विसर्जन स्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं या जो अपने घर के समीप विसर्जन करना चाहते हैं।

गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन मार्गों के पेंच वर्क का काम तेजी से जारी शहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन मार्गों के पेंच वर्क का काम तेजी से किया जा रहा है। इनमें नाका चन्द्रबदनी से बेटी बचाओ बाडा तक, नाका चन्द्रबदनी से एसएएफ रोड से कम्पू बस स्टैंड से थीम रोड अचलेश्वर मंदिर से इंदरगंज चौराहा से महल गेट शिंदे की छावनी से रामदास घाटी से जेल रोड, बहोड़ापुर चौराहा से आनंद नगर मेन रोड सागर ताल तक, महाराज बाडा से हनुमान चौराहा कटी घाटी बहोडापुर चौराहा आनंद नगर मेन रोड सागर ताल तक, महाराज बाडा से सराफा गस्त का ताजिया से छप्पर वाला पुल से शिंदे की छावनी से रामदास घाटी जेल रोड बहोडापुर से आनंद नगर से सागर ताल तक, सात नम्बर चौराहा से गोले का मंदिर चौराहा से जेसी मिल से सागर ताल तक, सात नंबर चौराहा से बारादरी चौराहा से गांधी रोड रेलवे स्टेशन से तानसेन रोड हजीरा चौराहा से सागरताल तक, दीनदयाल नगर से गोले का मंदिर चौराहा से जेसी मिल से चार शहर का नाक से सागर ताल की पेच रिपेयरिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही गणेश प्रतिमा विसर्जन के मुख्य मार्गों से जुडेन वाले सब मार्गों जिसमें महाराज बाडा से चिठनिश की गोठ कम्पू, नया बाजार, जिंसी नाला नम्बर 1,2,3, शिंदे की छावनी, महाराज बाडा से सराफा गस्त का ताजिया छप्पड वाला पुल, शिंदे की छावनी, जयेन्द्रगंज चौराहा से ऊंट पुल से गस्त का ताजिया से शिंदे की छावनी, गस्त का ताजिया से नई सडक हनुमान चौराहा कटी घाटी बहोडापुर सागरताल, नया बाजार से राज पाएगा रोड दाल बाजार जयेन्द्र गंज चौराहा अप टू सागर ताल, फूलबाग चौराहा से खेड़ापति कॉलोनी किला गेट सराफ बाजार कोटेश्वर मंदिर विनय नगर बहोड़ापुर चौराहा से सागरताल, फूलबाग चौराहे से पडाव चौराहा लक्ष्मणपुरा होते हुए तानसेन रोड हजीरा चौराहा से चार शहर का नाका रोड से सागर ताल तक, सात नम्बर चौराहा से बारादरी चौराहा गांधी रोड तक, एम एच चौराहा से बारादरी चौराहा तक सिंहपुर रोड, अग्रसेन चौक से सब्जी मंडी होते हुए छ: नम्बर चौराहा से सात नम्बर चौराह से गोले का मंदिर, बिरला नगर पुल से हजीरा चौराहा दुर्गादास प्रतिमा हजीरा चौराहा से चार शहर का नाक से सागर ताल, दुर्गादास प्रतिमा से चार शहर का नाका सागरताल, हजीरा चौराहा से किलागेट अप टू सागरताल तक पेच रिपेयरिंग का कार्य भी जारी है।

कोई भी दिव्यांग आवश्यक सहायक उपकरण अथवा योजना के लाभ से वंचित न

118 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण

राजगढ़

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं का विभागीय अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें। जिले का कोई भी दिव्यांग सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सभी जिला दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए एलिम्को के सहयोग से विकासखण्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर आवश्यक सर्वेक्षण भी किया जाए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा एलिम्को के सहयोग से दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री महीप कुशोर तेजस्वी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने 118 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए।

उप संचालक सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग श्री अर्पित गुप्ता द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यक्रम में 21 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटराईज्ड ट्राईसिकल, 16 दिव्यांगजनों को ट्राईसिकल, 40 को बैसाखी एवं 41 को कैलीपर्स प्रदान किए गए। इस दौरान एलिम्को के कृत्रिम अंग विशेषज्ञ श्री नीलेश कुमार भी मौजूद थे।।

रूस पर अब तक का भीषण हमला, 3 एयरपोर्ट बंद; 30 उड़ानें रद्द

यूक्रेन का मॉस्को सहित 10 शहरों पर एक साथ ड्रोन हमला

नई दिल्ली। पिछले ढाई साल से चल रहे रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने बीती रात मॉस्को पर भीषणतम हमला किया है। यूक्रेन ने 140 से अधिक ड्रोन जागकर रात भर रूस की राजधानी मॉस्को सहित कई क्षेत्रों को निशाना बनाया है। रूसी अधिकारियों ने मंगलवार को यूक्रेनी हमले की पुष्टि की है।मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि मॉस्को के पास रामेंस्कोए शहर में ड्रोन ने दो बहु-मंजिला आवासीय इमारतों को निशाना बनाया जिससे उनमें आग लग गई। उन्होंने बताया इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। वोरोब्योव ने बताया कि क्षतिग्रस्त इमारतों के पास पांच आवासीय इमारतों को खाली करा लिया गया है। हमले के कारण अधिकारियों को मॉस्को के पास स्थित तीन हवाई अड्डों – वनुकोवो, डोमोडेडोवो और जुकोवस्की को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रोसावियात्सिया के अनुसार, कुल 48 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों पर भेजा गया है, जबकि 30 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं। हमले के बाद एयरपोर्ट

के बाहर खड़ी बस में भी आग लग गई। मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा मॉस्को में ड्रोन हमले का मलबा शहर के बाहरी इलाके में एक निजी घर पर जा गिरा, लेकिन इसमे कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने मॉस्को की ओर बढ़ रहे दर्जनों ड्रोन को देखा जिन्हें शहर के करीब आते ही सेना ने मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने नौ रूसी क्षेत्रों में यूक्रेन द्वारा दागे गए कुल 144 ड्रोन को मार गिराया है।

रूस ने की आतंकवादी हमले से तुलना

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन ने राजधानी मॉस्को के अलावा रूस के कुर्स्क, बेलगोरोद, क्रालनोडार, वोरोनिश, बर्यांस्क, किरोव, कलुगा, तुला और ओर्योल समेत दस शहरों पर ड्रोन से हमले बोले हैं। रूस का कहना है कि ये हमले आतंकवादी हमले के समान हैं क्योंकि इसमें नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ, यूक्रेन का कहना है कि उसे रूस को गहरे जख्म देने और भीतरी इलाके में हमला करने का अधिकार है क्योंकि उसने 2022 में उसके ठिकानों पर हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया है।

बहुमंजिला इमारत के 5 फ्लैट नष्ट

रूस के एक चैनल ने बहुमंजिला आवासीय इमारतों से आग की लपटें निकलने के वीडियो पोस्ट किए हैं। इस पोस्ट में कहा गया है कि बहुमंजिला इमारत के 5 फ्लैट नष्ट हो गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन सीमा से टेक ब्रांस्क क्षेत्र में 72 यूक्रेनी ड्रोन को रोका गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कुर्स्क के ऊपर 14 और तुला के ऊपर 13 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा 5 अन्य इलाकों में 25 ड्रोन रोके गए हैं।

रूस ने किया जवाब हमला

मंगलवार को हुआ यूक्रेन का हमला सितंबर की शुरूआत में रूस के ऊर्जा और बिजली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद यह दूसरा हमला है। रूस का तुला क्षेत्र जो मॉस्को के उत्तर में स्थित है, वहां रूस का अहम ऊर्जा और ईंधन का केंद्र है। यूक्रेन ने इस केंद्र को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि रूसी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुला केंद्र को नुकसान नहीं पहुंच सका है। रूस ने भी इन हमलों का बदला लेने के लिए यूक्रेन के खारकीव और कई अन्य क्षेत्रों में जोरदार हमला बोला है। मंगलवार के हमलों के बारे में यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी है। दोनों पक्षों ने नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है, फिर भी दोनों पक्षों के हमलों में नागरिक मारे गए हैं।

हालात संभालने पहुंचे 2 हजार सीआरपीएफ जवान

मणिपुर में फिर तनाव, इंटरनेट और स्कूल-कॉलेज भी बंद

थॉमस एनगोंग (इंफाल)। मणिपुर सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं पर 5 दिन के लिए पाबंदी लगा दी है। सरकार ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे घृणा फैलाने वाले संदेश और तस्वीरें प्रसारित हो सकती हैं, जो कानून-व्यवस्था की स्थिति को और बिगाड़ सकती है। राज्य सरकार की तरफ से सभी स्कूल-कॉलेजों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

गृह विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाओं के जरिए फैलने वाले भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के कारण जनसाधारण की शांति और सामुदायिक सद्भाव को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस स्थिति को देखते हुए, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को 10 सितंबर की दोपहर 3 बजे से 15 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह आदेश उन मामलों को छोड़कर लागू होगा जिनके लिए राज्य सरकार ने छूट दी है। मणिपुर सरकार ने राज्य के सभी कॉलेजों और स्कूलों को गुरुवार तक बंद रखने का आदेश दिया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि छात्र आंदोलन और सरकार से बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के चलते कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे।

स्कूल बंद होने की अवधि गुरुवार तक बढ़ाई

8 सितंबर के सरकार के आदेश के तहत, सभी सरकारी और निजी कॉलेजों को बुधवार से गुरुवार तक बंद रखने की घोषणा की गई है। उसी दिन शिक्षा विभाग (स्कूल) ने भी स्कूलों की बंदी की अवधि को गुरुवार तक बढ़ा दिया है। स्कूलों को बढ़ती हिंसा के मद्देनजर इन्हें शनिवार से बंद किया गया था। केंद्र ने जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर में सुरक्षा ड्यूटी के

लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की दो नई बटालियन की तैनाती का निर्देश दिया है, जिनमें करीब 2,000 जवान होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि बटालियन संख्या-58 को वारंगल (तेलंगाना) से, जबकि बटालियन संख्या-112 को लातेहार (झारखंड) से भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक बटालियन को मणिपुर के कांगवई (चुराचांदपुर) जबकि दूसरी बटालियन को इंफाल के आसपास तैनात किया जाएगा।

एक बटालियन में 1 हजार जवान

सूत्रों ने बताया कि यह कदम जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य हिस्सों में तैनाती के लिए मणिपुर से असम राइफल्स की दो बटालियन को वापस बुलाए जाने के बाद उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इन दो नई बटालिन की सभी कंपनियां (लगभग 6-6) हिंसा प्रभावित राज्य के विभिन्न भागों में तैनात रहेंगी, जहां पिछले साल मई से जातीय संघर्ष जारी है, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सीआरपीएफ की एक बटालियन में करीब 1,000 जवान होते हैं। इस बल के पास मुख्य रूप से तीन तरह की जिम्मेदारी है, जिनमें पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटना, नक्सल-रोधी अभियान चलाना और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियान शामिल हैं।

पहले से ही बल की 16 बटालियन तैनात

सूत्रों ने बताया कि पिछले वर्ष की हिंसा के बाद मणिपुर में पहले से ही बल की 16 बटालियन तैनात हैं। हिंसा भड़कने से पहले मणिपुर में बल की लगभग 10-11 बटालियन थीं। एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने बताया, मणिपुर में सीआरपीएफ की प्रमुख भूमिका होगी। पिछले साल मई में मेइती और कुकी लोगों के बीच हिंसा भड़कने के बाद बल की नई बटालिन राज्य में भेजी गई थीं और अब बल को मजबूत किया जा रहा है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर हो सके। इस बीच, सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों और कुछ स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम इस सप्ताह के अंत में मणिपुर का दौरा करेगी। यह टीम पिछले कुछ दिनों में राज्य के कुछ क्षेत्रों में हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन और रॉकेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेगी।

मणिपुर में अत्याधुनिक रॉकेट के अवशेष मिले

इंफाल। मणिपुर में हाल ही में हुए ड्रोन और हाई-टेक मिसाइल हमलों के बाद अत्याधुनिक रॉकेट के अवशेष बरामद किए गए हैं। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के सेवानिवृत्त महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर के हाल में मीडिया को दिए साक्षात्कार में किए गए इस दावे को खारिज कर दिया कि राज्य में हमलों में किसी ड्रोन या रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया। नायर ने मणिपुर पुलिस को मेइती पुलिस भी कहा था।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) के. जयंत सिंह ने पत्रकारों से कहा कि यह बयान ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि यह असम राइफल्स के नहीं, बल्कि उनके निजी विचार हैं। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। ड्रोन और हाई-टेक मिसाइल हमलों के सबूत हैं। ड्रोन बरामद किए गए हैं।

नागरिक क्षेत्रों पर दागे गए अत्याधुनिक रॉकेटों के अवशेष बरामद किए गए हैं। ऐसे सबूतों के बावजूद यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रतिष्ठित कमांडर इस तरह का बयान दे रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) आई. के. मुइवा ने कहा कि हम यह स्पष्ट

कर देना चाहते हैं कि यहां कोई मेइती पुलिस या कुकी पुलिस नहीं है, बल्कि मणिपुर पुलिस है। मणिपुर पुलिस में नगा, मेइती, मणिपुरी मुस्लिम और गैर-मणिपुरी सहित विभिन्न समुदाय शामिल हैं। इस बल में ईसाई, मुस्लिम और हिंदू भी हैं। मणिपुर पुलिस को मेइती पुलिस बताना एक संकुचित मानसिकता को दिखाता है।

राज्य में जारी छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि रैली और धरना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। हम छात्रों से अपील करते हैं कि वे हिंसा न करें। कुछ लोग छात्रों को भड़का रहे हैं। हम सोशल मीडिया मंचों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काने वालों और छेड़छाड़ की गई तस्वीरों के साथ झूठे संदेश फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। ऐसी सामग्री के स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को थौबल में प्रदर्शनकारियों की ओर से चलाई गई गोली से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

पिछले साल मई से इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेई और आसपास की पहाड़ियों में रहने वाले कुकी लोगों के बीच जातीय संघर्ष में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस दौरान हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हिंसा की ताजा घटनाओं में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसमें ड्रोन और मिसाइल हमले भी शामिल हैं।

भारत निष्पक्ष देश होगा, तब आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब भारत निष्पक्ष देश होगा, तब कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, जो अभी नहीं है। राहुत गांधी ने यह टिप्पणी वाशिंगटन डीसी के प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों से बात करते हुए की।

दरअसल राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इसके जवाब में राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा, जब भारत निष्पक्ष होगा, तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। और भारत निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखेंगे, तो आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं; दलितों को 100 रुपये में से 5 रुपये मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है।

भारत का 90% हिस्सा भागीदारी करने में सक्षम नहीं

राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत में आगे कहा कि समस्या यह है कि भारत का 90 प्रतिशत हिस्सा भागीदारी करने में सक्षम नहीं है। भारत के हर एक कारोबारी नेता की सूची देखें, उसमें मुझे आदिवासी का नाम, दलित का नाम और मुझे ओबीसी का नाम नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। भारत में ओबीसी 50 प्रतिशत हैं, लेकिन हम लक्षण का इलाज नहीं कर रहे हैं। यही समस्या है। अब, यह (आरक्षण) एकमात्र साधन नहीं है। अन्य साधन भी हैं।

समान नागरिक संहिता पर राहुल गांधी ने नहीं की टिप्पणी

वहीं समान नागरिक संहिता के बारे में पूछे जाने पर, राहुल गांधी ने कहा कि वह इस पर तभी टिप्पणी करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि भाजपा का प्रस्ताव क्या है। उन्होंने कहा, भाजपा समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव कर रही है। हमने इसे नहीं देखा है। हमें नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए इस पर टिप्पणी करना समझ में नहीं आता। जब वे इसे लाएंगे, तब हम इसे देखेंगे और इस पर टिप्पणी करेंगे।

विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों में मतभेद थे, लेकिन वे कई बातों पर सहमत थे।

हम सहमत हैं कि भारत के संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। हममें से अधिकांश जाति जनगणना के विचार पर सहमत हैं। हम सहमत हैं कि दो व्यवसायी, अर्थात् अडानी और अंबानी, को भारत में हर एक व्यवसाय नहीं चलाना चाहिए। इसलिए, आपका यह कहना कि हम सहमत नहीं हैं, मुझे लगता है, गलत है।

कांग्रेस में नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने पर भड़के कार्यकर्ता

नई दिल्ली। जुलाना सीट से पहलवान विनेश फोगाट को टिकट मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस में नाराजगी नजर आ रही है। खबर है कि टिकट के कई उम्मीदवारों ने फोगाट को लेकर आयोजित कार्यक्रम से दूरी बना ली। साथ ही टिकट वितरण को लेकर एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। हाल ही में फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई हैं। उनके साथ पहलवान बजरंग पूनिया ने भी पार्टी का दामन थामा था। फोगाट के सम्मान में बख्ता खेड़ा गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जुलाना सीट से टिकट के कई दावेदार नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इन नेताओं में परमिंदर सिंह धुल, धर्मेंद्र धुल और रोहित दलाल समेत कई नाम शामिल हैं। कथित तौर पर ये नेता फोगाट को जुलाना सीट से उतारे जाने से नाराज हैं। स्थानीय नेताओं को लग रहा है कि उनके काम को नजरअंदाज किया गया और बाहर को लाया गया। हालांकि, इस दौरान टिकट के कुछ दावेदार रहने नेता कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। कहा जा रहा है कि फोगाट के कार्यक्रम में बेहद कम लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद वह पहली बार ससुराल पहुंचीं थीं। उन्होंने पौली गांव से रोड शो किया, जो रोहतक-दिल्ली हाईवे पर आता है।

एआईसीसी पर भी हुए थे प्रदर्शन

हरियाणा में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी मुख्यालय के बाहर रविवार को विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी में बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय नेताओं को वरीयता दिए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जताने के लिए प्रदर्शन किया। अधिकतर प्रदर्शनकारी हरियाणा के बवानी खेड़ा से थे और उन्होंने बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे की तख्तियां थाम रखी थीं।

पटौदी क्षेत्र के कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि पार्टी के नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख उदयभान की बेटी और दामाद को टिकट दिया जा रहा है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला-किलोई, फोगाट को जुलाना और राज्य इकाई के प्रमुख उदयभान को होडल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।

वन्यजीव विशेषज्ञ बोले- ईको सिस्टम और फूड साइकिल के लिए बेहद जरूरी, शेर और बाघ की तरह इन्हें भी सुरक्षित रखें

20 साल के बाद चंबल के बीहड़ में नजर आया भेड़िया

आगरा। बहराइच में भेड़िया का आतंक इन दिनों देशभर में सुर्खियों में है। मैनपुरी में भी भेड़िया दिखाई देने का दावा किया गया है। आगरा के बीहड़ और जंगलों से ये गायब हो चुके थे, लेकिन 20 साल के बाद चंबल के बीहड़ में भेड़िया नजर आया है। नेशनल चंबल सेंक्चुअरी क्षेत्र के नदगवां में भारतीय भेड़िया इस साल जनवरी और जुलाई में नजर आया है। इससे वन्यजीव विशेषज्ञ उत्साहित हैं।

लॉयन सफारी के शिक्षा अधिकारी कार्तिक द्विवेदी ने बताया कि इस साल जनवरी में जब वह नदगवां के इंटरप्रिटेशन सेंटर में एक कार्यक्रम में गए तो उन्हें चंबल के बीहड़ में 3 भेड़िये घूमते दिखे। इनमें से उन्होंने एक को सियार मानते हुए कैमरे में कैद किया। उन्होंने इसका फोटो नेशनल चंबल सेंक्चुअरी के पूर्व डीएफओ दिवाकर श्रीवास्तव को भेजा तो उन्होंने इसके भेड़िया होने की पुष्टि की। बाद में इसे देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भेजा गया, जहां विशेषज्ञों ने इसे भारतीय भेड़िया करार दिया। चंबल में यह 20 साल के बाद नजर आया। यहां लकड़बग्घा और सियार नजर आते रहे हैं, पर भेड़िया दिखना वन्यजीव विशेषज्ञों को चौंका गया।

ऑपरेशन में हो गए खत्म, संरक्षण की जरूरत

पूर्व डीएफओ दिवाकर श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे ईको सिस्टम और फूड साइकिल के लिए भेड़िया बेहद जरूरी है। यह नदियों के किनारे मांद बनाकर रहते हैं। चंबल में यह दिखा है तो इसे संरक्षण की जरूरत है। शेर और बाघ की तरह इन्हें भी सुरक्षित रखने की कवायद होनी चाहिए। पूर्व डीएफओ आनंद कुमार ने बताया कि 1994 में ऑपरेशन भेड़िया ने बड़ी संख्या में भेड़ियों को खत्म कर दिया, जबकि यह जंगल के लिए जरूरी हैं। बहराइच की घटना में भेड़ियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। यह गलत है, इनके संरक्षण की जरूरत है, न कि मारने की।

मांद में पानी घुसने पर निकलते हैं बाहर

पूर्व डीएफओ दिवाकर श्रीवास्तव ने बहराइच की घटना के बाद 1950 से लेकर अब तक हुई घटनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1950 के सितंबर में, 1994 में भी सितंबर में और अब 2024 में भी सितंबर में भेड़ियों के खिलाफ माहौल बना है। दरअसल, नदियों में बाढ़ के कारण भेड़ियों की मांद में पानी भर जाता है, इसलिए वह बाहर निकलते हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569